RESOLUTION RE ECONOMIC DEVELOPMENT OF BIHAR

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kamla Sinha, you can move your resolution.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Madam, I beg to move the following Resolution:--

"This House expresses its deep concern over the fact that despite fertile agricultural soil, adequate water resources and unparalleled mineral wealth, the State of Bihar remains one of the poorest States in the country and the main reason for its economic backwardness is the policies pursued by the Central Government in relation thereto due to which no infrastructure for economic progress has been developed in that State and therefore, urges upon Government to take necessary steps forthwith to undo the consistent neglect and economic exploitation of the people of Bihar."

3.00 P.M.

(The Vice-Chairman (Dr. Nagen Saikia) (in the Chair)

महोदय, मैं अपने इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ बातें रखना चाहती हूं। आप जानते हैं बिहार भौगोलिक दृष्टि से तो नहीं, लेकिन आबादी की दृष्टि से भारतवर्ष का दो नम्बर का राज्य है। सब से बड़ा राज्य इस देश में उत्तर प्रदेश है और उसके बाद बिहार है। जैसा कि मैंने अपने प्रस्ताव में कहा कि बिहार में कृषि योग्य जमीन बहुत है। अपार जल संपदा है, धरती के नीचे अपार खनिज संपदा है और इतनी संपदाओं के बावजूद बिहार आज सब से गरीब है। यह दुर्भाग्य की बात है इसको "आयरनी आफ् फेट" भी कहा जा सकता है, यह बिहार एक समय पूरे भारत का केन्द्र बिन्दु था। मगध साम्राज्य का वह केन्द्र स्थल था। भगवान बुद्ध के समय में बिहार प्रांत का नाम ही बिहार पड़ा इसलिए कि भगवान बुद्ध उस प्रांत में बारम्बार आते थे। प्रथम गणतंत्र वैशाली गणराज्य से अकसर वह गंगा पार हो कर आते थे, पटना। बिहार की अनगिनत जगहों पर उन्होंने बुद्ध विहारों की स्थापना की थी, उनके शिष्यों ने की थी और सम्राट अशोक ने की थी और इसके कारण इस प्रांत का नाम बिहार पड़ा। समय बदलता गया, जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के समय में भी और यूं कहा जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम कहते हैं उस आंदोलन में दानापुर के फौजी सिपाही आगे चले थे। मंगल पांडे को प्रतिवाद करने के लिए तोप के मुंह पर बांध कर अंग्रेजों ने उड़ा दिया था। कौन नहीं जानता है बाबू कुंवर सिंह को, 80 साल की उम्र के, लेकिन स्वतंत्रता के बलिदान में अपने को उन्होंने चढ़ा दिया था। उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उस आंदोलन में भी बिहार ने आगे बढ़ कर आत्माहुति दी। मुजफ्फरपुर में खुदी राम बोस अंग्रेजों को मार भगाने के क्रम में, एक अंग्रेज आफिसर के ऊपर बम चलाने के दोष में फांसी पर चढ़े थे अगस्त महीने में, अगस्त का महीना था, 18 साल का वह लड़का था। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का अग्रणी स्थान रहा है। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए तो चंपारण गए। चंपारण में नील करों का जो अत्याचार था उसको देखने के लिए बृज कुमार शुक्ल जी, उनको ले गए 1917 में, आचार्य कृपलानी भी रहे साथ-साथ अनेकों नेता वहां रहे और चंपारण सत्याग्रह से ही शुरू हुई भारतवर्ष गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरूआत। वह बिहार, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज किस स्थिति में है? जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो बिहार का स्थान सातवां था आर्थिक ढांचे में और आज सब से नीचे है। जैसा कि मैंने कहा हमारे प्रांत में अपार जल संपदा है। हिमालय से, नेपाल से अनगिनत नदियां आती हैं। कोसी, बागमती और कोसी की जो शाखा नदियां हैं वे आती

[Shrimati Kamla Sinha]

हैं और उत्तर बिहार के ऊपर बारम्बार कहर ढहाती हैं प्रतिवर्ष और उसके बाद मध्य बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन, एवं उनकी शाखा नदियां हैं । दक्षिण बिहार में कोइलकारो है, दामोदर है, दामोदर की शाखा नदियां हैं, स्वर्ण रेखा है और बहुतेरी नदियां हैं । इतनी जल संपदा से तो धरती सोना उगले, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार में सिंचित भूमि कितनी है ? कुल 27 लाख 95 हजार हैक्टेयर । आजादी के 44 साल बाद भी कुल सिंचित भूमि हमारे पास इतनी ही है । धान के उत्पादन की जमीन 61 लाख 73 हजार हैक्टेयर है । गेहूं का बीज 18 लाख 73 हजार हैक्टेयर जमीन में बोया जाता है । इसके अलावा दूसरी रबी की फसल और अन्य जो फसलें होती हैं, वह 9 लाख 85 हजार हैक्टेयर जमीन में होती हैं । महोदय, अगर खनिज संपदा को लें तो छोटा नागपुर का इलाका, दक्षिण बिहार का इलाका, मध्य बिहार का कैमूर पहाड़ का इलाका है, कौन ऐसा खनिज है जो हमारे बिहार में नहीं है । कोयला, लोहा, तांबा, मैंगनीज, आयरन ओर, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, चायना क्ले, माइका एक-एक चीज बिहार में पर्याप्त मात्रा में है । देश में जितना कोयला उत्पादन होता है, उसका 45 प्रतिशत केवल बिहार उत्पादन करता है । 62 हजार मिलियन टन कोयला प्रतिवर्ष बिहार में उत्पादन होता है और पूरे देश भर में 1 लाख 86 हजार मिलियन टन उत्पादन होता है । इस तरह एक-तिहाई कोयला बिहार उत्पादन करता है । इसी तरह 3 हजार 87 मिलियन टन लोहा बिहार उत्पादन करता है जबकि हिंदुस्तान का आंकड़ा 12 हजार, 398 मिलियन टन यानी एक-तिहाई लोहा बिहार में उत्पादन होता है । दूसरे, जैसे कि मैंने कहा अनेकों खनिज पदार्थ बिहार में हैं । तांबा जहां पूरे देशभर में 344 मिलियन टन का उत्पादन है, केवल बिहार में 154 मिलियन टन उत्पादन होता है इतने सब के बावजूद बिहार सबसे गरीब है, सबसे परेशान और भूखा है । इसका कारण क्या है ? महोदय, मैंने पहले ही अपने रिजोल्यूशन में कहा कि बिहार की गरीबी का कारण केन्द्र की उपेक्षा है । किसी भी प्रांत या किसी भी देश के विकास के लिए जो इंफास्ट्रक्चर चाहिए, जिस संरचना की आवश्यकता है उसमें सबसे पहले सड़क चाहिए । उसके बाद बिजली चाहिए, उसके बाद सिंचाई के साधन, फिर आवागमन के साधन, दूर-संचार के साधन, औद्योगिक विकास एवं व्यापार और उद्योग में पूंजी निवेश । इन्हें अगर हम एक-एक कर देखें तो क्या पाते हैं । ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो यह पाते हैं कि 1947 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 150 मेगावाट थी । टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी 150 मेगावाट थी और आजादी के 44 साल के बाद बिहार की कैपेसिटी 1550 मेगावाट है । यानी इन्स्टाल केपेसिटी के तहत पर केपिटा देशो 99 किलोवाट है । पूरे भारत वर्ष का ऊर्जा का उत्पादन क्या है ? 64,500 मेगलाट और पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर पर-केपिटा कंजम्पशन है 191 किलोवाट ।

महोदय, ने पहले ही बताहया कि बिहार प्रांत में अपार जल संपदा है । वहां हाइड्रल पावर हो सकता है । केन्द्रीय सरकार अगर चाहती तो हाइड्रल-पावर वहां हो सकता था, थर्मल पावर; सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी वहां बनाया जा सकता था । लेकिन, अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हो पाया । पावर के विषय में केन्द्रीय स्तर पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वह 33,663 करोड़ रुपया हुआ है और बिहार में केवल 1,312 करोड़ हुआ है यानी पावर के क्षेत्र में कुल तीन प्रतिशत इन्वेस्टमेंट बिहार में हुआ है ।

महोदय, अगर आप सड़क के मामले में देखेंगे कि नेशनल एवरेज क्या है सड़क का, तो देखेंगे कि प्रत्येक एक लाख की आबादी पर नेशनल एवरेज है 224 किलोमीटर और बिहार में है 120 किलो-मीटर । वर्ष 1974 के बाद बिहार प्रांत के लिए कोई नेशनल हाइवे नहीं बना । प्रांतीय सरकार ने अनेकों अनुशंसाएं की हैं

लेकिन केन्द्र ने उन्हें मंजूर नहीं किया। रेलवे का जाल बिछाने के लिए भी प्रांतीय सरकार ने अनेक अनुशंसाएं की हैं, जिसकी रेल मंत्रालय से **जांच**-पड़ताल भी हो चुकी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने मंजूर नहीं किया।

महोदय, मैं आपके सामने प्रति व्यक्ति योजना के द्वारा जो व्यय किया जाता है, उसको रखना चाहती हूं। प्रथम योजना के समय में प्रति व्यक्ति योजना व्यय जो हुआ था सभी प्रांतों में 39/- रुपए था, बिहार में 25/- रुपए था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आल-स्टेट्स का रेशो 52/- रुपए था और बिहार का था 40/- रुपए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बिहार का रेशो था 59/- रुपए और आल-स्टेट्स का रेशो था 93/- रुपए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 85/- रुपया बिहार के हिस्से में आया, जबकि नेशनल एवरेज 142/- रुपए आया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 तक की थी यह रेशो 190/- रुपए बिहार का हुआ और 327/- रुपए आल स्टेटस का हुआ। छठी योजना में 404/- रुपया बिहार का हुआ और 688/- रुपया आल स्टेटस का हुआ सातवीं योजना में 798/- रुपया बिहार का हुआ और आल स्टेटस हुआ 1022/ रुपया जैसे-जैसे योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास का काम होता गया, बिहार पिछड़ गया।

महोदय, मैं आपके सामने कुछ निम्न आय वाले राज्यों का आंकड़ा पेश करना चाहूंगी। निम्न आय वाले राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हैं। बिहार में जनसंख्या वृद्धि की दर तो 2.4 हो गई और खाद्यान्नों की वृद्धि दर हुई 1.1 और सिंचाई में वृद्धि हुई कुल मिलाकर 25 प्रतिशत। मध्य प्रदेश का क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि दर हुई 2.55 और खाद्यान्नों की वृद्धि की दर हुई 1.8, सिंचित क्षेत्र में इनका विकास हो गया 27 प्रतिशत। अन्य प्रांतों में बढ़ा है, उड़ीसा में भी बढ़ा है, उत्तरप्रदेश में भी बढ़ा है, राजस्थान में भी बढ़ा है, लेकिन बिहार का बढ़ाया नहीं जा सका। महोदय किसी भी प्रान्त या देश के स्वास्थ्य के निराकरण का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि वहां डाक्टर-पेशेन्ट रेश्यो क्या है। नेशनल रेश्यो क्या है? 2000 मरीज पर एक डाक्टर। बिहार का रेश्यो क्या है—4000 मरीजपर एक डाक्टर। प्लान का इन्वेस्टमेंट—जैसा मैंने बताया कि फस्ट प्लान में पर केपिटा इन्वेस्टमेंट हुआ 25 रुपया और नेशनल इन्वेस्टमेंट था 39 रुपया। 7वीं योजना में यह बिहार बढ़कर हो गया 758 रुपया और नेशनल इन्वेस्टमेंट था 1,012 रुपया।

महोदय, मैंने आपके सामने इन बिन्दुओं को इसलिए रखा ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि बिहार की हालत क्या है। मैंने आपके सामने यह कहा कि बिहार में सड़क 1974 से बन नहीं पाई। मैंने आपके सामने यह भी कहा था कि नेशनल हाइवे की सरकार के पास आवेदन दिया गया था, लंबित योजनाएं पड़ी हुई हैं, जिनको सरकार ने नहीं किया। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। राष्ट्रीय राजपथ के मास्टर प्लान में 1976 में कुछ पथों की सूची अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हुई है। एक तो लखनऊ से फरक्का वाया, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बक्सर, आरा पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं साहेबगंज। दूसरी सड़क गोविन्दपुर राष्ट्रीय पथ नम्बर 2 से वाया बीरपुर जाना था, नेपाल की सीमा तक। इसी तरह कई सड़कें पड़ी हुई हैं जो नेशनल हाइवे में भी आती हैं, नेपाल की सीमा तक। आप जानते हैं कि चीन और नेपाल की सीमा से सटी हुई होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह निहायत आवश्यक है कि इन लेटरल पथों का निर्माण हो जाए। इसी दृष्टिकोण से इन पथों के निर्माण के बारे में उस समय अनुशंसा की गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों यह अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। गंगा नदी की लंबाई बिहार में साढ़े चार सौ किलोमीटर है और केवल दो जगह में गंगा के ऊपर ब्रिज बना—मोकामा और पटना में। कई जगह गंगा के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए अनुशंसा की हुई है, अभी तक केन्द्रीय सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया।

मैंने जैसा कहा कि संरचना में रेल सेवा भी एक आवश्यक सेवा है । बिहार में रेलवे लाइन बिछाने की बात योजना में दी गई थी, वह 1974-75 से लेकर अभी तक पड़ी हुई है, एक भी रेलवे लाइन पर काम नहीं किया गया--समस्तीपुर रेलवे लाइन है, समस्तीपुर-दरभंगा है, मुजफ्फरपुर-दरभंगा है, रांची-गिरिडीह है, अनेक हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहती । ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया ।

महोदय, किसी भी प्रान्त के विकास का एक बड़ा आवश्यक अंग होता है औद्योगिक विकास और जैसा मैंने शुरु में कहा कि ऑयरनी आफ फेट, बिहार में देश का 45 प्रतिशत कोयला उत्पादित होता है और बिहार में ऊर्जा नहीं, थर्मल पावर नहीं । बिहार में ऊर्जा की कमी के कारण उद्योग चल नहीं पाता है । केन्द्र को जहां पूंजी-निवेश करना चाहिए था उद्योग के मामले में, वह भी नहीं हो पाया । पिछले 25 सालों में कोई महत्व-पूर्ण पूंजी-निवेश हुआ ही नहीं । एक जो बड़ा कारखाना खोला गया था--बरौनी तेलशोधक कारखाना । उस समय कहा गया था कि यह पैट्रो केमिकल्स कारखाना बनाया जाएगा, इसका और विस्तार होगा लेकिन 25 सालों में यह काम नहीं हुआ । एक जिंहाई लोहा बिहार में उत्पादित होता है खनिज सम्पदा से, लेकिन एक मात्र लोहे का कारखाना बोकारो का लगाया गया 25 साल पहले । यह ठीक है, गुलाम भारत में जमशेद जी टाटा ने इस सदी के शुरु में जमशेदपुर की स्थापना की थी, टाटा नगर की स्थापना की थी । निजी उद्योगपतियों ने उस समय बिहार के अंदर जो खनिज सम्पदा है उसको पहचाना था और उसको पहचानते हुये लोहे क कारखाना और उसके साथ के संयंत्रों की जमशेदपुर में रचना हुई थी । सीमेंट का कारखाना--सोन कैली सीमेंट फैक्टरी सन् 1919 में लगायी गयी थी । डालमिया नगर का कारखाना था, जहां बीस हजार लोग काम करते थे, एक उद्योग समूह था यह उद्योग भी पिछले आठ साल से बीमार । पड़ा हुआ है, बन्द है । इससे चार जिलों की अर्थ-नीति प्रभावित हुई है, लोग भूखे मर चाहे हैं । लेकिन के द्रीय स्तर से उद्योग के क्षेत्र में जो पूंजी निवेश करना चाहिये था यह उद्योग के क्षेत्र में केवल पूंजी निवेश हुआ है--बरौनी तेल शोधक कारखाना खोलशा गया और एक बोकारो का कारखाना खोला गया । बिहार सरकार ने बारम्बार आवेदन किया कि केन्द्रीय औद्योगिक योजना के जरिये और कल-कारखाने खोले जायें । जमालपुर में रेलवे की एक फैक्टरी की, वह फैक्टरी नहीं चल पाती ठीक से । प्रान्तीय सरकार ने यह निवेदन किया था कि इस फैक्टरी को ठीक से चालू कराया जाये, इसकी सृजन क्षमता को बढ़ायेंगे जाये ताकि इससे रेलवे का कोच बनने लगे । यह सम्भव था, लेकिन केन्द्रीय सरकार की दुरंगी नीति के कारण यह नहीं हो सका ।

आपको नदियों के बारे में अगर मैं बताऊं, तो सोन नहर 11 साल की पुरनी नहर है । यह कहना शायद अनुचित न होगा कि पिछली सदी के शुरुआत में एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था, जिसका जिक्र आता है, आप में से जिस किसी ने बंकिम चन्द्र को पढ़ा होगा । बंकम चन्द्र ने "आनन्द मठ" नामक पुस्तक लिखी है, इस "आनन्द मठ" में उस अकाल का जिक्र है । उस अकाल के बाद तीन काम हुये थे । एक तो, सिंचाई की आवश्यकता को पहचानते हुये अंग्रेजों ने उस समय सोन नहर से सिंचाई की व्यवस्था की थी, जिससे चार जिलों में सिंचाई होती थी, निश्चित सिंचाई की योजना बनी थी । दूसरा, उस समय फेमिन कोड बनाया गया था महोदय, जो आज भी परिवर्तित नहीं हुआ, और तीसरा, पटना में अनाज के एक भंडार का निर्माण हुआ था, वह आज भी है, जो सौ साल साल से ज्यादा पुराना है । भण्डारण के काम में उसका इस्तेमाल होता था । तो महोदय सबसे बड़ी बात तो यह हुई थी कि बंकम चन्द्र ने "आनन्द मठ" लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था--"वन्देमातरम्" तो महोदय, यह 117 साल पुरानी सोन सिंचाई की व्यवस्था जर्जर हो गयी । इसमें सोन आधुनिकीकरण की योजना केन्द्रीय सरकार के पास

लम्बित पड़ी हुई है—सोन मोडर्नाइजेशन प्लान। उस समय तीन सौ करोड़ की यह योजना थी। आज इस योजना का आकार बढ़कर कई गुना अधिक हो गया है। इंफ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, डिवेल्यूएशन आफ रुपी हुआ है। आप जानते हैं कि यह चक्रवृद्धि की दर से मंहगाई बढ़ती ही जा रही है। इस बीच में 1973 में एक काम और हुआ था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को जल मिले, इसके लिये बाण सागर योजना का एग्रीमेंट हुआ। बाण सागर योजना के तहत रिहंद जलाशय में जो पानी है उससे बिहार को सोन नहर चलाने के लिये एक निश्चित सीमा तक पानी देने का एग्रीमेंट हुआ, जिससे 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उपलब्ध हो सकती थी और बाण सागर के इकरारनामा के हिसाब से कम से कम 67.5 लाख एकड़ फीट पानी बिहार को मिलना ही था। लेकिन इसमें हुआ क्या? इस मामले में भी केन्द्रीय सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी की। रिहांड के पानी की यह योजना थी कि बिहार में सिंचाई के लिए पानी देने के बाद ही दूसरा काम होगा लेकिन उस पानी का भी इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के लिए किया गया और सिंगरौली में एन०टी०पी०सी० द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता का सृजन किया गया। वहां उस पानी का इस्तेमाल शहर के लिए भी होने लगा और बिहार में पानी की कमी हो गई। लेकिन दुर्भाग्य यह कि उस बिजलीघर से हमें बिजली नहीं मिलती है। उस बिजलीघर से बंबई को बिजली जाती है, उस बिजलीघर से दूसरे हिस्सों में बिजली जाती है लेकिन बिहार को उसका हिस्सा नहीं मिलता।

महोदय, सोन में जब ज्यादा पानी आएगा तो बाढ़ आएगी और बिहार डूबेगा और हमेशा बिहार की ही डूबने की हालत है। महोदय, मैं आज की स्थिति आपको बताऊं। बिहार में आज खेत सूखे पड़े हैं, धान नहीं रोपा जा सका। हमारे जो बिहार के साथी यहां बैठे हैं, वे इसी की गवाही देंगे। धान नहीं रोपा जा सका लेकिन सड़कों पर पानी चल रहा है, बाढ़ आई हुई है। गंगा नदी पटना शहर को डुबोने पर लगी हुई है और यह पानी हम रोक नहीं सकते क्योंकि अंतरराज्यीय नदी है। हम उद्गम स्थल पर बांध नहीं बना सकते। और बांध कहां बांधा गया है फरक्का में बांध बांधा गया और उससे बिहार को नुकसान हुआ। मुझे नहीं मालूम बंगाल के सदस्य यहां हैं या नहीं, उनको इस बात से नाराजगी होगी लेकिन फरक्का के बांध के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में सिल्टेशन आ गया। नदी का पेट ऊंचा होता जा रहा है भरता जा रहा है जिससे नदी के बहाव में कमी आ गई और बाढ़ का प्रकोप बढ़ता गया।

इसके बाद फरक्का बांध से एक नुकसान और हुआ। आप जानते हैं नदी से कुछ मछलियां आती थीं जैसे हिल्सा मछली और झींगा मछली। ये मछलियां समुद्री मछलियां हैं और ये मीठे पानी में अंडे देने के लिए ऊपर आती हैं। अब इन मछलियों की भी कमी हो गई। एक तरफ तो बाढ़ का खतरा पैदा हो गया और दूसरी तरफ कुछ खाद्य वस्तुओं की कमी हो गई और नदी का पेट ऊंचा हो गया जिसके कारण आस-पास के सारे गांव डूबने की स्थिति में आ गए। तो यह जो परेशानी है, यह केंद्रीय सरकार की नीतियों के कारण ही बिहार को भुगतनी पड़ रही है लेकिन मैं आपका ध्यान इससे भी भयंकर बात की ओर दिलाना चाहती हूं।

मैंने शुरू में कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा खनिज संपदा है—लोहा, पिग आयरन और इन चीजों का एक तिहाई उत्पादन बिहार करता है और इन की

[Shrimati Kamla Sinha]

से कल-कारखाने चलते हैं। महोदय, 11 जून, 1956 को केंद्रीय सरकार ने टोन्टोन भूषण चरो के वित्त मंत्रित्व में एक तोड़ि घोषणा की--फ्रेट इक्वलाइजेशन पालिसी। यह करिश्मा है। दूर-दराज कहीं पर भी रेलगाड़ियों से यह खनिज भेजा जाएगा जैसे लोहा, पिग आयरन और इसको कोयला कम होगी क्योंकि उनको यह भेजा ले जाना है दूर-दराज के प्रांतों में, उनके विकास के लिए और बिहार जो उत्पादक प्रांत है या पूरे पूर्वांचल के जो उत्पादक प्रांत हैं--बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनको उस पालिसी के चलते नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि हम उत्पादन तो करते रहे, आज भी कर रहे हैं लेकिन इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पालिसी के कारण बिहार को नुकसान होता जा रहा है और सारी इंडस्ट्रीज, जितनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये सब ईस्टर्न रीजन से उठकर वेस्टर्न रीजन में चली गई। मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वेस्टर्न रीजन में ही केंद्रित है। कितने प्रतिशत है ? 30.9 प्रतिशत।

नार्दर्न रीजन में 30.8 परसेंट है, साउदर्न रीजन में 22.7 परसेंट है और बिहार जो कि लोहे और कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तथा अन्य खनिजों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वहां पर यह 12.6 परसेंट है। यह सीधे सीधे बिहार के प्रति अन्याय है। बिहार सरकार ने यह डिमांड की है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन की पालिसी को आप दुरुस्त कीजिए। जो नजदीक के प्रान्त हैं, जहां उत्पादन होता है उनको खनिज महंगा दो और जो दूर ले जाएं उनको फ्रेट इक्वलाइजेशन करके सस्ता दो। अगर आपको फ्रेट इक्वलाइजेशन की पालिसी लागू रखनी है तो जो चीज हम बिहार में पैदा नहीं कर रहे हैं, जैसे काटन है, आयरनओर है, कैमिकल्स हैं जिनके लिए हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, उनका भी फ्रेट इक्वलाइज कर दीजिए। नहीं तो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पालिसी को कैंसिल कीजिए अन्यथा बिहार को कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोयला बिहार में सबसे ज्यादा पैदा होता है लेकिन केन्द्र सरकार का यह कानून है कि कोयला चूंकि बाइटल इंडस्ट्रियल रॉ मैटीरियल है इसलिए इसको वैगंस से भेजे जाएंगे और वैगंस से वह दूर चला जाएगा। पास के जो क्षेत्र हैं वहां रोड ट्रांसपोर्ट से कोयला जाएगा। इसलिए बिहार में कोयला की खपत है उसकी कीमत ज्यादा होती है और बिहार से जो बाहर जाता है उसकी कीमत कम है। अतः फ्रेट इक्वलाइजेशन की समस्या बिहार के लिए गंभीर समस्या है।

तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कोयले की रॉयल्टी के बारे में। बिहार में कोयला कई कैटेगरीज का होता है। जो कोकिंग कोल है जो मैटलर्जिकल कोयला है जिसका इस्तेमाल थर्मल पावर स्टेशन में और लोहे के कारखानों में होता है उसकी रायल्टी कम देते हैं। बिहार के मुख्य मंत्री ने जब कहा कि मैं अनशन पर जाऊंगा तो आपने कोयले की रायल्टी का रिवीजन किया है। कोयले पर सैस लगाया जाता था आपने कानून बनाकर बिहार सरकार के सैस लगाने के अधिकार को छीन लिया। मिनरल डेवलपमेंट ऐक्ट के तहत आपने इस अधिकार को छीन लिया। अच्छा होगा कि आप कोयले और अन्य खनिजों के ऊपर सैस लगाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों को वापस कर दें। आप तो आराम से बैठे हैं यहां लेकिन एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। जब तक बिहार और ईस्टर्न रीजन के लोग सचेत नहीं थे तब तक उनका शोषण होता रहा लेकिन अब उनमें चेतना आ गई है, वह अपने अधिकार की बात करते हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहती हूं और वह यह है कि पूरे देश में जो पूंजी निवेश है बैंकों में, जिनको डेबिट-क्रेडिट रेशियो कहते हैं, उसका 1 रुपए में से केवल 35 परसेंट बिहार में निवेश होता है, 65 परसेंट बिहार से बाहर चला जाता है, बंबई, मद्रास, गुजरात आदि में खर्च होता है।

यह सरासर अन्याय है । इसको सुधारेंगे नहीं तो बहुत परेशानी होगी । पहले पहल 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय इस समस्या को उठाया गया था और 60 प्रतिशत बैंकों का हमारा जमा बिहार के खाते में खर्च हुआ था । बिहार में उसका पूंजीनिवेश होता था लेकिन उसके बाद फिर पुनर्मूषक: भव: यानी फिर हम बैंक टु द पेविलियन हो गये । वही 35 पैसे हमारे भाग में और वही 65 पैसे जो हम कमाई कर के देते हैं उसकी हिस्सेदारी आपकी हो जाती है यह नहीं चलने वाला है । कुछ दिन पहले हमारे उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा था कि उड़ीसा के प्रति अगर इस तरह का भेदभाव बरता जायेगा तो उड़ीसा मजबूर होगा यह कहने के लिए कि हम स्वतंत्र हो जायेंगे ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आप मत कहियेगा ।

श्रीमती कमला सिन्हा : यह बात भारतवर्ष के कुछ प्रांत कहने वाले हैं । इस तरह का भेदभाव बरता गया तो यह लक्षण शुरू हो जायेगा । यह लक्षण शुरू हुआ है जम्मू-कश्मीर में, यह लक्षण शुरू हुआ है पंजाब में, यह लक्षण शुरू हुआ है पूर्व प्रांतों में, यह लक्षण शुरू हुआ है दक्षिण में । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं कि आज अगर सरकार नहीं चेती, अगर हमारा उचित हिस्सा हमें नहीं मिला, बिहार को और पूर्वांचल को उसका हिस्सा नहीं मिला तो रूस का नक्शा आपने देखा, पूर्वी यूरोप का नक्शा देखा । प्रथम विश्व युद्ध के पहले का नक्शा बन रहा है यहां । 50 साल, 100 साल पहले का नक्शा बन रहा है । जब बाई-पोलर वर्ल्ड था उस समय एक तरफ सोवियत रूस था और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा था---आमने-सामने । शीत युद्ध बरसों चलता रहा । वह बाई-पोलर वर्ल्ड खत्म हो गया है । रूस का एक-एक अंग अलग हो रहा है । अलग हो रहा है और अपने को स्वतंत्र घोषित कर रहा है । भारतवर्ष में हम चाहते हैं यहां संघीय ढांचा बना रहे । लेकिन संघीय ढांचे में आबादी के लिहाज से और हमारी कमाई के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से यानी हम जो खनिज सम्पदा देते हैं, हम जो अपनी कमाई से पैसा देते हैं, हम जो धनोपार्जन करके देते हैं उसका हिस्सा हम को मिलना चाहिए हमारे विकास के लिए । बिहार का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा । देश के किसी भी कोने को पीछे रखकर, पिछड़ा रख देश आगे नहीं बढ़ सकता । एक अंग को पैर के नीचे रखकर दूसरा सिर उठा कर खड़ा नहीं हो सकता । देश का मतलब है पूरी एक एन्टीटी, एक समूह, एक समग्रता यह समग्रता तभी सफल हो सकता है जब हम सब लोग साथ मिलकर चलें । नहीं तो मजबूर मत कीजिए यह बात कहने के लिए कि हम भी अब आजादी का झंडा लहरायेंगे, हम भी अलग हो जायेंगे । रूस का नक्शा हमारे सामने है । इसलिए मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने रवैये को बदले । योजना मद में बिहार का जो हिस्सा है वह उसको दिया जाए। पूर्वांचल का जो हिस्सा है वह उसको दिया जाए । हमारी खनिज सम्पदा के बदले जो हमारा उचित मुआवजा बनता है वह दे । रायल्टी के मामले में प्रत्येक दिन दो करोड़ रुपये का बिहार को घाटा हो रहा है । यह घाटे की भरपाई की जानी चाहिए ।

प्रो. चन्द्रेश पी. ठाकुर : (बिहार) : बिहार सरकार भी कुछ करे इसके लिए कुछ कहिये ।

श्रीमती कमला सिन्हा : फ्रेट इक्वलाइजेशन के बारे में मैंने कहा । इसे स्क्रैप किया जाए । बैंक में जो हमारा हिस्सा है उसका पूंजीनिवेश बिहार में किया जाए । कोयले की एड-वलरम रायल्टी दी जाए । सैस लगाने का हमें अधिकार दिया जाए । अगर यह नहीं किया जायेगा तो बिहार की आर्थिक संरचना में सुधार नहीं हो पायेगा । अगर सुधार नहीं हो पायेगा तो भारत का विकास भी पिछड़ा हुआ रहेगा । धन्यवाद ।

*The question was proposed.*

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKLA):** Dr. Ratnakar Pandey. You have 15 minutes.

**डॉ० रत्नाकर पाण्डेय** (उत्तर प्रदेश) : इतने बड़े प्रदेश पर चर्चा हो रही है और 15 मिनट में क्या कहा जायेगा ।

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA):** Your time-limit is 15 minutes. I will go by the rules. The rule book is with me.

**डा. रत्नाकर पाण्डेय :** : हमारी गरीबी की रेखा के नीचे जिंदा रहने वाला प्रांत है माननीय उपसभाध्यक्ष जी, प्राइवेट मेम्बर बिल पर बोलने में समय की कमी न हो, इस पर आप सम्मान के साथ विचार करें श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जो प्राइवेट मेम्बर प्रस्ताव रखा है उसी के संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । उन्होंने गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का निष्पादन करने का जो संकल्प लिया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उर्वर कृषि भूमि, यथेष्ट जल-संसाधन और अतुलनीय खनिज-सम्पदा होने के बावजूद बिहार राज्य देश के सर्वाधिक निर्धन राज्यों में से एक है और इसके आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य के संबंध में चलाई गई नीतियां हैं, जिनके कारण उस राज्य में आर्थिक प्रगति के लिए कोई अवसंरचना विकसित नहीं हो पाई है । अभी मैं देख रहा था, कमला जी सीजन्ड राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने रूस का जिक्र किया । रूस में क्या हो रहा है ? वहां पर स्वायत्ता की आंधी आई है । लेकिन भारतवर्ष की संस्कृति में "एकोहम बहुस्याम: " कहा गया है । मैं एक हूं, मेरे बहुत से रूप हैं । हमारी राष्ट्रीयता सार्वभौमिकता में संनिविष्ट हुई है । भारत के स्वतंत्र होने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बृहत्तर आसाम जिसके अन्य सात सिस्टर स्टेटस हुए हैं, इनकी बड़ी उपेक्षा हुई है । तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रान्तों में जितने औद्योगिक तीर्थ स्थापित हुए, जितने बड़े बड़े कल-कारखाने स्थापित किये गये उसका कारण यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरु जी ने जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं का श्रेष्ठतम कार्य निष्पादन हो सकता था, सब का, भारत के बृहत्तर हित को ध्यान में उन स्थानों पर नियोजन और निवेश किया जो दिल्ली से दूर थे और जो सारे देश की बहु-आयामी संस्कृति और सभ्यता को और पूरी पोपुलेशन को जोड़कर रख सकते थे । केन्द्रीय सरकार ने उपेक्षा की या नहीं की, मैं नहीं कहता । लेकिन मैंने देखा है, जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री थे तो उनके दल के बिहार के एक सांसद ने उनको पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि हमारी उपेक्षा हुई है । उस उपेक्षा को आप नियोजित कीजिये । श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का आश्वासन तो आया, लेकिन वे कुछ करने में असमर्थ रहे । केन्द्र में कोई भी सरकार हो, प्रश्न उसका नहीं है । प्रश्न इस बात का है कि बिहार में साम्यवाद अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और एक क्रांति आ रही है । कहीं बोडो आंदोलन चल रहा है तो बिहार में भी जो आदिवासी एरियाज हैं उसमें स्वायत्ता की मांग हो रही है । अभी माननीया प्रवक्ता महोदया ने कहा कि अलग होने की काश्मीर से लेकर हर जगह एक दीवार खड़ी करने की साजिश चल रही है और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि जो अन्य हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त हैं, अगर इन्होंने आपस में दीवार खड़ी करने की कोशिश की तो यह ठीक नहीं होगा । हम अभाव में भी अपने स्वभाव को, हम अपनी कमियों में भी अपनी परिपूर्णता को, हम शोषण में भी अपनी समाजवादिता को व्यक्त करते रहे हैं । इसीलिये देश जुड़कर रहा है । उड़ीसा सबसे गरीब प्रांत है और उसके बाद शायद बिहार का नंबर आता है ।

**एक माननीय सदस्य :** बिहार पहले नम्बर पर है।

**डा. रत्नाकर पाण्डेय** : पहले उड़ीसा था अब बिहार हो गया है। फिर उत्तर प्रदेश आता है फिर असम आता है। अब शिक्षा अनिवार्य विषय है। लेकिन हम देखते हैं 5 सितम्बर 1991 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वोट क्लब नई दिल्ली में वित्त रहित शिक्षा नीति का अर्थी जलूस और पुतला दहन। संसद के समक्ष प्रदर्शन कर रहे बिहार राज्य सबद्ध डिग्री/महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के लोग आंदोलन किये हुए हैं। उपसभाध्यक्ष जी आप ऐसा कोई प्रांत नहीं पायेंगे जहां वित्त रहित शिक्षा नीति चालू हो। बिहार ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां अध्यापन कार्य तो करवाते हैं हजारों अध्यापक पड़े हुए हैं और उनकी एडहाक नियुक्तियां हुई हैं। पिछले दिनों वहां के अध्यक्ष आये थे और उन्हें मैंने शिक्षा मंत्री अर्जुन सिह जी के पास भेजा था। महोदय वित्त रहित शिक्षा नीति कभी सुनने में नहीं आई देखने में नहीं आई। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो माफिया काम कर रहे हैं बिहार में अभी भी दर्जनों ऐसे लोग मिल जायेंगे जो कि विधायक भी हैं मंत्री भी हैं और अध्यापक भी हैं प्रिंसिपल भी हैं रजिस्ट्रार भी हैं वाइस चांसलर भी हैं लेकिन वहां हजारों अध्यापक ऐसे भी हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती है और उन्हें कहा जाता है...

**श्रीमती कमला सिन्हा** : प्वांइट आफ आर्डर। इस तरह का स्वीपिंग रिमार्क माननीय सदस्य को नहीं करना चाहिये कि विधायक भी हैं मंत्री जी भी हैं और माफिया भी हैं।

**डा. रत्नाकर पाण्डेय** : हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो माफिया हैं...

**श्रीमती कमला सिन्हा**: अगर इस तरह का आरोप लगायेंगे तो आपको उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज करती हूं। आप इस तरह का एलीगेशन नहीं लगा सकते कि बिहार में विधायक मंत्री शिक्षा माफिया हैं। और अगर कर रहे हैं तो इसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। आन दि फ्लोर आफ हाउस मैं इनको चैलेंज करती हूं कि या तो वे इसको प्रमाणित करें नहीं तो इसको विदड्रा करें।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : यह पंपलेट है बिहार राज्य शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ पटना का और इसमें है कि शिक्षा माफियाज पर कार्यवाही और शिक्षा में व्याप्त अनार्किज्म को समाप्त करने और स्वस्थ शैक्षिक वातावरण कायम करने हेतु...

**श्रीमती कमला सिन्हा**: अगर कोई पर्चा निकाले तो बाहर उस पर कार्यवाही हो सकती है लेकिन सदन के प्रोटेक्शन में रहकर आप इस बात को मत कहिये। क्योंकि अगर आप कोई बात सदन में कहेंगे तो इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। यह गलत बात कह रहे हैं। सदन के अंदर प्रोटेक्शन में रहकर इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : ये तो बड़ी लड़ाई करती है कैसे बोलियेगा।

**श्रीमती कमला सिन्हा**: अनुचित बात मत कहिये।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : मैं जो कुछ कह रहा हूं और संसद को अधिकार है, यहां पर भूतपूर्व ला मंत्री और प्लानिंग मिनिस्टर बैठे हुए हैं। आप देख लें कि बोट क्लब पर बिहार राज्य सबद्ध महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का कैंप लगा हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाज पर कार्यवाही करो और शिक्षा में व्याप्त अनार्किज्म को समाप्त करो, स्वच्छ वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में कायम करो और वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करो।

THE VICE-CHAIRMAN: (DR. NAGEN SAIKIA): She says, you should with draw it.

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** : मेरे कहने का आशय यह है कि जो बिना तनख्वाह के अध्यापन करा रहे हैं सरकार, चाहे कोई सरकार हो, बिहार की सरकार हो या किसी और प्रांत की सरकार हो, यह बंद होना चाहिये। एडहाक नियुक्तियां करके वर्षों से लोगों का शोषण हो रहा है। न छात्र पढ़ रहे हैं और न अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बिहार में बहुत सी संस्थायें चलाई जाती हैं चाहे सरकार किसी की भी रहे यह व्यक्तियों और दलों का प्रश्न नहीं है लेकिन बहुत से लोग जो मोनोपोली किये हुए हैं एजुकेशन में मेडिकल के नाम पर, इंजीनियरिंग के नाम पर, पोलीटकनिक्स के नाम पर, बिहार में ये लोगों से कैपीटेशन फीस लेते हैं। संस्थान चल रहे हैं विधान सभा में भी हैं अन्य जगह हैं **(व्यवधान)**

**श्रीमती कमला सिन्हा** : कर्नाटक में नहीं ले रहे हैं क्या?

**डा० रत्नाकर पाण्डेय**: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बिहार में मेरी ससुराल भी है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश का पुराणों से ले कर ऐतिहासिक संबंध है। अगर सीता बिहार में न पैदा होती तो रामायण की रचना न होती और सीता का हरण न होता, लंका दहन न होता पृथ्वी पर से राक्षसी वृत्तियों का विनाश न होता। बिहार की मैं तारीफ करता हूं। बिहार ने भगवान बुद्ध को पैदा किया। बिहार ने चाणक्य को पैदा किया। बिहार ने चन्द्रगुप्त को पैदा किया। शिखा खोल कर के चाणक्य ने शासन नहीं किया चन्द्रगुप्त को अपने फालोअर को शासक बनाया। आज बिहार में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और वहां के खनिज उत्पादनों, कृषि योग्य भूमि और रत्नगर्भा धरती के उत्पादनों से सारा राष्ट्र और विश्व प्रभावित है। लेकिन वहां पर शोषण का जिस तरह से जाल फैला हुआ है भारत स्वतंत्र हो चुका है लेकिन वहां आज भी पराधीनता की आंधी चल रही है। बड़े बड़े कुलक बड़े बड़े जमींदार आज भी बंधुआ मजदूरों के रूप में लोगों का उपयोग कर रहे हैं जिनकी हजारों एकड़ जमीन कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस के नाम पर लैंड सीलिंग कानून से बचने के लिए कर दी गई है। चाहे कोई भी शासन हो बिहार में मूक हो कर उसको देख रहे हैं। इस तरह की चीजें समाप्त होनी चाहियें। बिहार में एक स्थान मध्यपुरा है। वहां एक बार चुनाव के दिनों में राजीव गांधी यात्रा करने गए। उनकी टोली पर अटैक हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी जी गये उनकी टोली पर अटैक हुआ। वहां जनतंत्र में मोनोपोली चालू की गई। बिहार में किस मुख्य मंत्री के समय में ला एंड आर्डर कितना ठीक रहा और कितनी लूट मार कम्यूनल डिसटर्बेंसेज हुए, ऐसी परिस्थिति हुई जिस पर नियंत्रण न हो सके यह सब परिस्थितियां, एकाधिकार, मोनोपोली, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस का वातावरण जितना इस समय बिहार में है उतना इसके पहले कभी भी नहीं था। **(व्यवधान)**

**मौलाना अबदुल्ला खान आजमी**: (उत्तर प्रदेश) : 40 साल तक नहीं था, सही कह रहे हैं आप।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय**: (उत्तर प्रदेश) : यह भी बिहार के हैं।

**डा. रत्नाकर पाण्डेय**: आपकी भी ससुराल बिहार में है लगता है। मैं यह कह रहा था कि जनतंत्र में मत देने का अधिकार सब को प्राप्त है और मतदान का नियंत्रण कर के लोगों को वोट डालने से रोक कर के, गम्भीर परिस्थितियां पैदा कर के, डरा-धमका कर के जो काम किये जाते हैं वह उचित नहीं होते हैं। सारा एजुकेशन सिस्टम बिहार में लैप्स हो गया है। 6 साल से बहुत से विश्वविद्यालयों के रिजल्ट नहीं निकले हैं। हमारे बिहार के मित्र लोग इससे सहमत होंगे। आज तक बिहार में एक भी सेंट्रल यूनीवर्सिटी नहीं दी गई है। क्या पाप किया है?

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

साढे सात करोड़ आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार है लेकिन क्या यह इस लायक भी नहीं है कि एक सेंट्रल यूनीवर्सिटी बिहार में दी जा सके। हजारों अध्यापक वहां बिना तनख्वाह के पढ़ाते हैं। उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या पढ़ायेंगे, क्या आतंकवादी और क्रिमिनल नहीं होंगे और छात्रों को वे कौन सा उपदेश वे दे पाएंगे? उनसे बेगार ली रहे हैं। शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक सेंट्रल यूनीवर्सिटी खोली जाए। बूथ कैप्चरिंग की प्रथा वहां बहुत दिनों से है। इस प्रथा को इलेक्शन कमीशन, ला सिस्टम और जो भी उत्तरदायी लोग हैं वे रोकें ताकि निर्भीक हो कर के जनतंत्र में विश्वास करते हुए लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। बिहार में, जैसा मैंने पहले कहा, सब से अधिक खनिज सम्पदा है। राज्य का उत्तरी हिस्सा समतल है और कृषि के लिए उपयुक्त है और दक्षिणी इलाके में वन तथा खनिज सम्पदा है। इसके बावजूद भी यह राज्य इतना पिछड़ा क्यों रहा। कृषि उत्पादन पर अनावृष्टि, अतिवृष्टि का प्रभाव तो पड़ता ही है और करोड़ों रुपये की फसल प्रतिवर्ष बरबाद होती है। 40-44 साल के बाद भी सोन नदी में बाढ़ आती है या गंगा नदी बढ़ती है, अर्थात नदियों के पानी को बांटकर हम सिंचाई के लिए उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ़ खनिज सम्पदा का भरपूर उपयोग तो हम करते हैं लेकिन औद्योगिक विकास की गति इतनी धीमी है कि राज्य के औद्योगीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों की मान्यता है कि अगर दक्षिणी बिहार का उपयोग सही ढंग से कर दिया जाए तो सम्पूर्ण बिहार की जनता को अकेले दक्षिणी बिहार खिला सकता है, अगर ढंग से खेती आदि वहां हो। इसकी आबादी 7 करोड़ से ऊपर है। राज्य की कुल जनसंख्या का 22.7 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिक है जबकि देश में औद्योगिक श्रमिकों की औसत संख्या 33.4 परसेंट है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 12.5 परसेंट है जबकि राष्ट्रीय औसत संख्या 23.3 परसेंट शहरों में रहने वालों की है। औद्योगिक श्रमिकों की प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता सिर्फ 417 रुपये है जबकि औसत राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति 79 रुपये है। औद्योगिक श्रमिकों की प्रति व्यक्ति मासिक आय 458 रुपये है जबकि राष्ट्रीय औसत आय 664 रुपये है। इस राज्य में विभिन्न उद्योगों की स्थापना एवं उनकी संरचना एक गम्भीर समस्या है। प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योगों की संख्या काफी कम है। आयरन स्टील कम्पनी टाटा, लोकोमोटिव की इंजीनियरिंग कम्पनी जमशेदपुर, सिन्द्री का खाद कारखाना, भारी मशीनरी उपकरण और ढलाई कारखाना, राँची-इस्पात संयंत्र बोकारो, तेल शोधक कारखाना, बरौनी, इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी भूरी? बारूद कारखाना, गोमिया, कागज कारखाना, डालमिया नगर और इसके अलावा बहुत से प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं। बिहार में बड़े व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की संख्या जो मोनोपोली ले सकते हैं, बड़े उद्योग कहे जा सकते हैं चाहे निजी क्षेत्र में हों चाहे सरकारी क्षेत्र में, एक दर्जन से अधिक हैं।

1984 के आंकड़े मेरे पास हैं। लघु उद्योगों में यहां 45;349 कारखाने थे जिनमें 2,368 पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या थी। यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसके इर्द गिर्द के राज्यों में संतोषजनक औद्योगिक विकास हुआ है जबकि इस राज्य से कम खनिज उन राज्यों में है। पश्चिमी बंगाल में जो बंगाल में ही है, प्रतिरक्षा उद्योगों को छोड़कर 6,324 बड़े तथा मध्यम श्रेणी के और 1,84,264 लघु उद्योग कार्यरत हैं। उड़ीसा में 316 बड़े व माध्यम उद्योग हैं तथा 1985 तक ... (समय की घंटी) 50,466 लघु उद्योग स्थापित हो चुके थे। माननीय सभापति जी, इस डिबेट में थोड़ा सा हमें बोलने

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

का मौका दीजिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्योंकि बड़ी तैयारी की है हमने।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You take three minutes.

DR. RATNAKAR PANDEY: I will take ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Every Member is entitled to get fifteen minutes. It is the rule. There is a time limit in the Private Members' Business also.

DR. RATNAKAR PANDEY: I will try to conclude as early as possible.

मध्य प्रदेश में 261 बड़े तथा मध्यम और 1,19,706 लघु उद्योग कार्यरत हैं। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार में संचालित 49 लोक उपक्रम पब्लिक सेक्टर में हैं। 43 ऐसे हैं जिनमें मार्च 1986 तक 448.45 करोड रुपये का घाटा हुआ और पिछले 2 वर्षों में यह घाटा बढ़कर 156.45 करोड़ रुपये हो गया है। एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति के निवेश के बावजूद बिहार सरकार को लोक उपक्रमों से हर साल औसतन 80 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। यही नहीं दो यूनिट्स जल विकास बोर्ड और दुग्ध विकास बोर्ड वहां बंद हो चुके हैं और अन्य 6 उपक्रम बंद होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से यह जानने की कोशिश की जा सकती है कि यह घाटा कैसे हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार से यह जानने की कोशिश की जा सकती है कि यह घाटा कैसे हुआ। यह न कह कर टाला जाए कि यह प्रांतीय सरकार का सब्जेक्ट है। क्या प्रांतीय सरकार की नीतियां गलत थीं या उपक्रम के गठन का निर्णय गलत था या उत्पादन करने वाले कर्मचारी ईमानदार नहीं थे या कामचोर, दामचोर और नामचोर लोग इन उपक्रमों को घटाने में सहयोग करने लगे? ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी लोक उपक्रमों को बिहार में अपनी जायदाद समझते हैं और राज्य के लोक उपक्रम सरकारी अधिकारियों का वह चरागाह बन गया है जिसमें मंत्री से लेकर संतरी तक सम्मिलित रहते हैं। बिहार में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की भी वही स्थिति है जो बिहार के लोक उपक्रमों की है। हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में 70 दिनों तक हड़ताल हुई और 21 हजार कर्मचारियों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया गया। इसकी स्थापना से लेकर अभी तक 500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिससे आर्थिक स्थिति काफी डांवाडोल है। भारी इंजीनियरिंग निगम में सन् 1971 से अब तक 246.85 करोड़ रुपये का कुल विनियोजन हुआ परन्तु उसे मुनाफे के स्थान पर, विनियोग के स्थान पर दुगुना घाटा हुआ। अगर भारी इंजीनियरिंग निगम की बर्बादी की तह में देखा जाए तो उसके लिए निगम का इंतजाम जिम्मेदार है। 80 वर्ष से टाटा स्टील में 1986-87 में 1.907 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इस अवधि में टाटा स्टील ने 12 करोड़ रुपये आयकर के रूप में और 8-9 करोड़ रुपये बिक्री कर के रूप में और 75 से 80 करोड़ रुपया उत्पादन कर के रूप में सरकार को भुगतान किया। इसके बावजूद टाटा स्टील ने 87.52 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इससे स्पष्ट है कि टाटा स्टील का संचालन स्वच्छ ढंग से हो रहा है। लेकिन जो सरकारी उपक्रम हैं उनमें बराबर घाटा जा रहा है। मुझे देखने का मौका मिला है बहुत से सरकारी उपक्रमों को, कोल इंडिया, स्टील इंडिया के बिहार के और भारी रकम राजस्व के रूप में प्राईवेट जो संस्थान हैं वह हमें देते हैं, अब वह निरंतर घाटा देते हैं तो उसके लिए एकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए, चाहे केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हों, चाहे प्रांतीय सरकार के उपक्रम हों, जिनके जिम्मे वह काम लगाया जाए

4.00 P.M.

[ डा० रत्नाकर पाण्डेय ]

वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और उत्पादन में अगर घाटा देते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महोदय, जिस तरह से औद्योगिक विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। अनेक उद्योगपतियों ने अपना कारखाना वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस तरह का आतंक, दबाव, चंदा वसूली जबर्दस्ती वहां होती है। माफिया गैंग के लोगों से बहुत से नेताओं का संबंध है। पिछले प्रधान मंत्री, आपने अखबारों में पढ़ा होगा माननीय चन्द्रशेखर धनबाद में कोल माफिया के गिरोह के साथ, प्रधान मंत्री के रूप में उनका समर्थन करते रहे, उन्हें व्यवसाय दिलवाते रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** महोदय, यह एलीगेशन है, यह आरोप है।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय :** यह सत्य है। .....(व्यवधान)

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** यह आरोप है, उसका नाम....(व्यवधान) लेना होगा...(व्यवधान) मेरी उसमें आपत्ति है.....(व्यवधान)

**डा० रत्नाकर पाण्डेय :** घर गए थे और मैं वहां गया था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि हमें विवश किया गया, प्रधान मंत्री ने विवश किया कि हम वहां जाएं और ऊस गैंग के, माफिया के यहां जा करके....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Don't invite all these things. . .

DR. RATNAKAR PANDEY: I have not mentioned any names. It is a fact...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGESH SAIKIA): You try to conclude ...

DR. RATNAKAR PANDEY: I am trying to conclude, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGESH SAIKIA): O. K. You have already taken twenty-four minutes.

DR. RATNAKAR PANDEY: I want two minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGESH SAIKIA): No, only one minute. If you don't conclude, I will call the next speaker.

**डा. रत्नाकर पाण्डेय :** सर, उत्तर प्रदेश, बिहार इसने बराबर दान दिया है संस्कृत, कला, साहित्य, अध्यात्म के क्षेत्र में, जो विभूतियां पैदा की हैं, उन्हीं से सारा देश जुड़ा हुआ है। राम, कृष्ण, जनक, बुद्ध की यह धरती है और संस्कार उत्पन्न करने वाला काम इन राज्यों में हुआ है। इसलिए बिजली, सड़क और पानी तीन समस्यायें अगर बिहार की हल हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। नए खुलने वाले उद्योगों पर से राजनीतिज्ञों का नियंत्रण हट जाए और सरकारी उपक्रम हों, चाहे प्राईवेट उपक्रम हों, उन सब को कच्चा माल मिले और मजदूरों की भागीदारी उसमें हो, तब जा करके कुछ वहां हो सकता है। इतना ही नहीं औद्योगिक क्षेत्र में हिंसा और अशांति का बोलबाला बिहार में है। डालमियां की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है जहां कि 10 हजार मजदूर बेकार हैं और खाने के अभाव में मर रहे हैं। अपनी अस्मिता लुटाकर लोग अपना पेट पाल रहे हैं। डालमियां नगर में ऐसी प्रतिकूल और अमानवीय परिस्थितियों में बिहार सरकार को सीधे इंटरवेंशन करना चाहिए। बिहार में तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता कोई नीति सफल नहीं हो सकती जब तक कि विकास को हतोत्साहित करने वाले ऊर्जा संकट से बिहार को नहीं उबारा जाता।...(समय की घंटी)...वहां ऊर्जा लागत का प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिशत से 72 प्रतिशत अधिक है। जब तक बिहार को अधिक-से-अधिक बिजली नहीं देंगे तब तक वहां उत्पादन नहीं हो सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Shrimati Sarala Maheshwari.

DR. RATNAKAR PANDEY: I am going to conclude, Sir.

जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वह गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं। मुट्ठीभर आतंकवादी उन योजनाओं को रोक लेते हैं और गरीबो के लिए जो योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बनायी जाती हैं, वह उन तक नहीं पहुंचती हैं।

अंत में, अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि बिहार में जो लूटमार, गुंडागर्दी, शासन की ओर से आतंकवाद फैलाया गया है, उसका एक मात्र उपाय है कि वर्तमान मुख्य मंत्री को सस्पेंड किया जाए और पूरी एसेंबली भंग की जाए। वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नए चुनाव कराए जाएं, तब वहां जनतंत्र की आस्था प्रगट होगी। . . . (**समय की घंटी**) . और जब जनतंत्र की आस्था प्रगट होगी तब जाकर व्यवस्थित ढंग से निर्भीक होकर बिहार की 7 करोड़ से ज्यादा जनता अपना पार्टिसिपेशन कर सकेगी और गरीबी रेखा से ऊपर उठकर, अमीरों को नीचे लाकर एक समाजवादी व्यवस्था होगी। आतंकवाद और हिंसा की छाया में हम बिहार की प्रगति नहीं कर सकते।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव . . . **(व्यवधान)** . . . की आतंकवादी व हिंसक सरकार का अंत हो, नए चुनाव की मांग करते हुए इसका समर्थन करता हूं।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Mr. Vice-Chairman, this should be expunged. The latter portion of his speech must be expunged.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, you will have to decide.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I shall look into it.

SHRIMATI KAMLA SINHA: This must be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I shall look into it.

DR. RATNAKAR PANDEY: Why? The Chief Minister should resign, Sir.

**श्रीमती कमला सिन्हा** : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस सदन में नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

**डा० रत्नाकर पाण्डेय** – हमने सीता का नाम लिया, जनक का नाम लिया, यह तो सौभाग्य है कि आतंकवादी मुख्य मंत्री का नाम भी ले रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I shall go through the record. If there is anything objectionable it will be expunged.

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती कमला सिन्हा ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के साथ, प्रस्ताव की मूल भावनाओं के साथ मैं खुद को संबद्ध करती हूं।

इसी संदर्भ में मुझे ब्रिटेन के एक बहुत बड़े पत्रकार डेविड सेलबोर्न की एक उक्ति याद आती है। जब हमारे हिंदुस्तान पर आपातकाल के दहशतनुमा बादल छाए हुए थे, उस समय श्री सेलबोर्न यहां आए थे और उन्होंने हमारे देश के संदर्भ में एक किताब लिखी थी "एन आय टू इंडिया"। उस किताब का पहला वाक्य यह था कि, "भारत एक ऐसा समृद्ध देश है जिसके लोग गरीब हैं।" उपाध्यक्ष महोदय, आज विश्व के संदर्भ में हमारे हिंदुस्तान की यही स्थिति है कि हमारा हिंदुस्तान प्राकृतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद हकीकत यह है कि आज भी विश्व का सबसे पिछड़े हुए देशों में, विश्व के सबसे गरीब देशों में एक है। इसके कारणात यह हैं कि हमारे देश ने साम्राज्यवाद के इशारों

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

पर जो नीतियां तय कीं, जो असमान संधियां कीं और विकास का जो रास्ता अख्तियार किया, उस रास्ते पर चलते हम अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। जो स्थिति विश्व के संदर्भ में हमारे देश की है वही स्थिति हमारे राष्ट्र के संदर्भ में बिहार की है। बिहार की धरती रत्नगर्भा धरती है, जिसमें कोयला रूपी काला हीरा छिपा हुआ है, जहां लौहा छिपा हुआ है, जहां नाना तरह के अयस्क छिपे हुए हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी बिहार हमारे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है।

महोदय, कहने को तो बिहार को देश के तमाम हिस्सों से जोड़ दिया गया है, तमाम हिस्सों में रेलवे जाती है। लेकिन, रेलवे का काम क्या है? रेल बिहार से कोई तैयारशुदा माल हिंदुस्तान के दूसरे भागों में आपूर्ति नहीं करती है, बल्कि वह रेल सबसे ज्यादा श्रम-शक्ति का निर्यात हिंदुस्तान में सब जगहों पर करती है। बिहार से जो रेलें जाती हैं वह बिहार से कच्चे माल को ढोती हैं और जब आती हैं तो तैयार माल लेकर आती हैं। यही कारण है कि बिहार जैसा राज्य, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है उन प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल न कर पाने के कारण पिछड़ा हुआ है।

महोदय, यह हकीकत, यह सच्चाई इस बिहार के साथ नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के साथ है। मंत्री महोदय हंस रहे हैं, मैं आती हूं हकीकत पर। हमारा पश्चिमी बंगाल जो आजादी के पहले तक औद्योगिक क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पर था, प्रथम नंबर पर था, इन सालों में आज पिछड़ते-पिछड़ते ऐसी स्थिति तक आ पहुंचा है, जिसे निश्चित रूप से सकारात्मक नहीं कहा जा सकता।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सवाल हमारे देश के केन्द्र-राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। हमारी केन्द्र सरकार की नीति क्या है? वह राज्यों को किस तरह से देखती है? वह विकेन्द्रीयकरण की बात करते रहे, गांधी और नेहरू गांव के नीचे के स्तर तक सत्ता को ले जाने की बात करते रहे। लेकिन, आजादी के 44 वर्षों में हमने देखा कि सत्ता गांव के स्तर तक नहीं पहुंची बल्कि सत्ता सिर्फ केन्द्र में सिमटती चली गई। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, सारी की सारी सत्ता केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में सिकोड़ ली। हम जो अपने भारत की संस्कृति पर गर्व करते हैं, गर्व से कहते रहे हैं कि हमारे देश की संस्कृति में, विविधता में एकता है, आज आजादी के 44 वर्षों बाद हमारे देश के सामने, भारत वर्ष के सामने यह सवाल खड़ा हुआ है कि हमारा देश एक रहेगा या नहीं? हमारा देश अखंड रहेगा या नहीं? निश्चित रूप से हमें उन कारणों में जाना पड़ेगा कि कौनसे ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर आ खड़े हुए हैं कि जगह-जगह, हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से पृथकतावाद की, क्षेत्रीयवाद की आवाज आ रही है? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर तरह-तरह के पृथकतावादी आंदोलन खड़े हो रहे हैं। इन तमाम आंदोलनों की जड़ों को हमें देखना है।

महोदय, हमारे देश का इतिहास बताता है कि हमारे यहां जो शासक पार्टी रही, उस शासक पार्टी ने अपने निहित स्वार्थों को खातिर, अपने क्षुद्र राजनीति स्वार्थों की खातिर हमारे देश के योजनाबद्ध विकास के साथ गद्दारी की है, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी। अन्यथा क्या कारण था कि पश्चिमी बंगाल जैसा राज्य आज इस स्थिति में आ पहुंचा है? क्यों

पश्चिमी बंगाल की जो तमाम वृहत योजनाएं थीं, जिनके लिए पश्चिमी बंगाल की जनता लड़ती रही, चाहे वह हल्दिया पैट्रो-केमिकल हो, चाहे बकेश्वर हो, चाहे इलेक्ट्रोनिक्स प्लांट हो, तमाम प्रकल्प केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए लटके हुए पड़े रहे? पन्द्रह सालों में, बीस सालों में उन पर जो खर्चा होने वाला था, उनकी लागत दुगुनी-तिगुनी हो गई। लेकिन, केन्द्र सरकार ने सिर्फ निहित राजनीतिक स्वार्थों के चलते इनको अनुमति नहीं दी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि किस तरह पिछले चंद वर्षों में राज्यों के अधिकारों को सीमित करते-करते राज्य-सरकारों की भूमिका को एक कलेक्टर की भूमिका में बदल दिया गया। राज्य सरकारों के वित्तीय-अधिकारों में इतनी कटौती की गई कि राज्यों के सारे के सारे हाथ बांध दिए गए और तमाम राज्यों ने, जिसमें पश्चिमी बंगाल की सरकार प्रमुख थी, इस बात को उठाया था कि इस तरह अगर केन्द्र राज्यों के साथ बर्ताव करे तो हिंदुस्तान का एक रहना खतरे में पड़ जाएगा। और इस मांग के चलते सरकारिया आयोग का गठन किया गया और सरकारिया आयोग के सामने विभिन्न राज्य सरकारों ने, विभिन्न मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने बयान दिए थे और सरकारिया आयोग ने इस बात को नोट किया था कि केन्द्रीय सरकार की नीति के चलते आज विभिन्न राज्यों की यह स्थिति हो गई कि केन्द्र सरकार जिस ढंग से राज्यों को संचालित कर रही है, उसमें निहित स्वार्थ काम कर रहे हैं, राष्ट्र के वृहत्तर स्वार्थ काम नहीं कर रहे। मैं आपके सामने सरकारिया आयोग के सामने पश्चिम बंगाल सरकार ने जो राज्यों के हितों के संबंध में बयान दिया था, उसको उद्धृत करना चाहूंगी। इसमें कहा गया है कि :-

> "राज्यों के हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण तभी हो सकेगा, जब निष्पक्ष रूप से निर्धारित साधनों के अंतःकरणों के संबंध में सुधारी हुई व्यवस्थाओं के साथ-साथ उनके वित्तीय क्रिया-कलाप के क्षेत्र को परिवर्धित करने के लिए भी समान ध्यान दिया जाए। इसमें वित्तीय शक्तियों के वितरण का पुनः रेखांकन किया जाए, जैसा कि संविधान में राज्यों के पक्ष में निरूपित किया गया है।"

लेकिन, उपसभाध्यक्ष महोदय, इन तमाम सिफारिशों के बावजूद हकीकत यह है कि हमारी केन्द्र सरकार द्वारा कई आयोग गठित किए जाते हैं, कई कमेटियां गठित की जाती हैं, लेकिन उन तमाम कमेटियों और आयोगों की सिफारिशें सरकार के ठंडे घरों में रख दी जाती हैं, उन पर कोई अमल नहीं होता है। उन पर सोचा भी तब जाता है जब मंडल कमीशन की तरह कोई ज्वालामुखी फूटता है, अन्यथा मंडल कमीशन की रिपोर्ट 15 साल तक पड़ी रही, उस पर कोई ध्यान नहीं गया कांग्रेस की सरकार का। तो यह हमारी सरकार का जो काम करने का तरीका है, इसके चलते आज यह स्थिति आई कि राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकारों को लगातार कमजोर किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में मैं पश्चिम बंगाल की सरकार ने सरकारिया आयोग के सामने जो कहा था कि किस तरह से राज्यों के वित्तीय अधिकारों में कटौती की जा रही है, उद्धृत करना चाहूंगी: -

> "राज्यों को जिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका कारण केन्द्र की पूंजीगत प्राप्तियां और प्रत्यक्ष बाजार ऋणों, दोनों में राज्यों का हिस्सा कम होना है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते होंगे कि वित्त आयोग जो सिफारिश करता है, केन्द्र सरकार को स्वाभाविक रूप से वित्त आयोग की उन सिफारिशों को मानना चाहिए, लेकिन हमने देखा

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

है कि केन्द्रीय सरकार वित्त आयोग की सिफारिशो को भी मानने से इंकार करती रही है। 8वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की थी, उसके तहत पश्चिम बंगाल सरकार को एक निश्चित राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने अपनी मनमर्जी से उसमें से 300 करोड़ रुपए निकाल दिए और इसी तरह से अन्य राज्यों से कुल 1500 करोड़ रुपए निकाल दिए गए। उपसभाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता दी जाती है राज्यो को, क्या केन्द्र सरकार यह मल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन उसे करना चाहिए आर्थिक सहायता देते समय? कोई मानदंड तैयार करना चाहिए कि किस राज्य को किस आधार पर आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो मानदंड क्या होना चाहिए कि वह राज्य जो सबसे कमजोर राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, उसको अधिक आर्थिक सहायता मिले। लेकिन मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि हुआ बिल्कुल इससे उल्टा है। वे राज्य जो पिछड़े हुए थे, वे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों को केन्द्र की तरफ से सबसे कम आर्थिक सहायता मिली।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं यह बतलाना चाहूंगी कि पूरा पूर्वांचल, जो पिछड़ा हुआ है, उसके पीछे केन्द्र सरकार की सौतेली नीतियां हैं। फेट इक्वेलाइजेशन की नीति या समान भाड़ा ढुलाई, यह पूरे पूर्वांचल के विकास के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप सोचिए कि जो चीज बंगाल में पैदा होती है, जो चीज बिहार में पैदा होती है, जो चीज उड़ीसा में पैदा होती है, वह उसी दाम पर पश्चिम बंगाल में भी बिके और सुदूर गुजरात में भी बिकेगी, लेकिन अगर गुजरात से कोई चीज पश्चिम बंगाल में आती है, उड़ीसा में आती है, तो उसका पश्चिम बंगाल को ज्यादा दाम देना पड़ेगा। यह कौन सा न्याय है? इसके आधार पर आप क्या समान न्याय कर सकते हैं? हमारे हिंदुस्तान के जो राज्य हैं उन राज्यों के साथ आप न्याय कर सकते हैं? और फेट इक्वेलाइजेशन की नीति के विरुद्ध, इस नीति को खत्म किया जाये, खासकर पश्चिम बंगाल की सरकार एक लम्बे अरसे से मांग करती आ रही है लेकिन इस मांग की ओर केन्द्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और अभी भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार राज्यों के साथ खिलवाड़ करती है? बिहार ने मामला उठाया कोयले की रायल्टी का, उसके हक में कुछ संशोधन कर दिया गया, पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़ दिया गया? यह कौन सी, नीति है, यह कौन से पैमाने हैं चीजों के आंकने के? सरकार को अपने यह पैमाने बदलने होंगे, यह मानदण्ड बदलने होंगे कि अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को लेने से पहले आप सोचिये कि इस निर्णय से कौन-कौन से राज्यों को फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, इसके बहुतर परिणाम क्या हैं? लेकिन हमारी केन्द्रीय सरकार सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के तहत ही काम करती रही है और इसके चलते आज हमारा हिंदुस्तान इस मुकाम पर आ गया है। अभी हमारे पाण्डेय जी नही हैं, शायद चले गये, जो चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की बात करते हैं और जनतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं। बिहार की सरकार को तोड़ दीजिये, जनतंत्र मजबूत हो जायेगा। अतीत में भी इन्होंने ऐसे बहुत काम किये हैं, इससे जनतंत्र मजबूत नही होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सवाल इस बात का है कि केन्द्र राज्य संबंधों

का अगर सही ढंग से पुनर्विन्यास नहीं किया गया तो निश्चित रूप में हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता खतरे में पड़ जायेगी और इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप राज्यों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाईये, राज्यों को एक कलेक्टर की भूमिका में मत बदलिये -(घंटी)- राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाइये। राज्य अपने संसाधनों का इस्तेमाल सही ढंग से कर सकें, उनकी योजनाओं को आप यहां पर ठंडे घर में पड़ा मत रहने दीजिये। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की खातिर देश के बृहत्तर स्वार्थों से अगर खेला जायेगा तो उपसभाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप में यह भारत जैसे विशाल देश के लिये, भारत जैसे इतने बड़े जिसका संगठनात्मक ढांचा है वह संगठनात्मक ढांचा सिर्फ कहने का रह जायेगा, वह हमारा संगठनात्मक ढांचा कमजोर होता जा रहा है और अगर हमारे देश का संगठनात्मक ढांचा कमजोर होता है तो हमारा देश निश्चित रूप से एक नहीं रह सकता। इसलिये मैं फिर इस प्रस्ताव के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगी कि इन संबंधों को, यह जो केंद्र राज्य संबंध है बहुत नाजुक हैं, एक राज्य पानी के लिये लड़ रहा है, दो-दो राज्यों में पानी के लिये लड़ाई होती है। अंतर्राज्यीय परिषद में मामले जाते नहीं हैं, मामले अटक जाते हैं, तो इन तमाम चीजों को सही ढंग से सुलझाने की प्रक्रिया अपनायें और सत्ता का ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीयकरण करें, केन्द्रीयकरण की इस प्रक्रिया को खत्म करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कमला सिन्हा जी ने जो गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, इसमें इस बात का उल्लेख है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य के संबंध में चलायी गयी नीतियां हैं, इस बात का उन्होंने उल्लेख किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है और मेरे सामने वह आंकड़े हैं, जब स्टार्ड प्रश्न 158 पूछा गया था तो उसमें यह बताया गया था कि सभी प्रांतों की जो पापुलेशन बिलो पावरटी लाईन है उसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा यदि किसी राज्य में है तो वह उड़ीसा है, यह 44.7 प्रतिशत है और उड़ीसा के बाद गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग अगर किसी राज्य में हैं तो वह बिहार के लोग हैं, जो 40.8 प्रतिशत हैं। इस 40.8 प्रतिशत में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वह 42.7 प्रतिशत हैं और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वह 30 प्रतिशत हैं।

माननीय, यह बड़ी अजीब बात है कि जिस राज्य में अत्यधिक खनिज संपदा है, अत्यधिक संसाधन हैं और जिसमें सबसे ज्यादा जल संसाधन हैं, वह राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यह बहुत अफसोसजनक बात है और इस पर गौर किया जाना जरूरी है।

महोदय, जहां भारत में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 1750 रुपए है वहां बिहार में रहने वाले आदमी की औसत आमदनी केवल 958 रुपए है। तो ये सारे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बिहार निस्संदेह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है लेकिन अगर यह देखा जाए कि समय-समय पर बिहार को केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों के तहत क्या-क्या मदद की गई, कौन-कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में क्या-क्या राशि आवंटित की गई तो निश्चित रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बिहार यद्यपि पिछड़ा हुआ राज्य है लेकिन बिहार की उपेक्षा नहीं की गई है, बिहार के साथ भाई-भतीजावाद नहीं किया गया है।

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत रेलवे विभाग आता है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आती है । मेरे पास आंकड़े हैं कि बिहार में प्रति सौ स्क्वेयर किलोमीटर पर जो रेलवे को सुविधा है वह 3.06 किलोमीटर है जबकि जो नेशनल एवरेज है वह 1.89 किलोमीटर प्रति सौ स्क्वेयर किलोमीटर है । तो नेशनल एवरेज से ज्यादा बिहार को दी जाने वाली रेलवे को सुविधा का एवरेज बढ़ रहा है । अगर हम सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की बात करें तो जो नेशनल एवरेज आता है नेशनल हाईवेज का वह 0.98 किलोमीटर आता है और बिहार को कितना प्रदान किया गया है ? बिहार को 1.26 किलोमीटर प्रदान किया गया है । तो ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि जहां तक केंद्रीय सरकार की तरफ से सुविधाएं प्रदान करने की बात है, केंद्रीय सरकार की तरफ से मदद करने की बात है तो उसकी तरफ से कोई उपेक्षित व्यवहार नहीं किया जा रहा है ।

महोदय, बिहार में जो प्रति हजार बर्थ रेट है वह 34.4 है जबकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर है वह 3.05 है । तो राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा बर्थ रेट बिहार में है । डैथ रेट जो नेशनल लेवल का है वह 10.2 है और उसके विपरीत बिहार में जो डैथ रेट है वह 12.1 है । इसी प्रकार लिट्रेसी रेट यदि हम देखें तो उसका जो नेशनल एवरेज है वह 52.11 है जबकि बिहार में जो लिट्रेसी का रेट है वह 38.51 है । तो जब हम जन्म दर की बात करते हैं तो वह नेशनल एवरेज से ज्यादा है या जब हम मृत्यु दर की बात करते हैं तो वह नेशनल एवरेज से ज्यादा है और जब हम लिट्रेसी की बात करते हैं तो वह नेशनल एवरेज से कम है । तो इन सारी चीजों पर भी हमको ध्यान देना होगा जब हम बिहार के पिछड़ेपन की बात करें । वहां उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, उन पर भी गौर करना जरूरी है ।

माननीय, जब कोई उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करता है तो वह देखता है जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जैसे बिजली है, पानी है, रोड है, कानून और व्यवस्था है क्या वह राज्य सरकार उसे उपलब्ध करा सकती है या नहीं । बिहार के बारे में जिक्र किया गया है वहां के उद्योगपतियों की मानसिकता का जिक्र किया गया है कि आज स्थिति यह है कि बड़े बड़े उद्योगपति वहां उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जब वहां की कानून और व्यवस्था पर गौर करते हैं, वहां के सौहार्दपूर्ण वातावरण पर नजर डालते हैं तो वह पीछे हट जाते हैं कि वहां उद्योग स्थापित किया जाए या नहीं । अगर किसी राज्य में उद्योग स्थापित नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाएगा । इसलिए हमें उद्योग स्थापित करने के लिए मानसिक दृष्टि से जरूर विचार करना चाहिए और वे सभी सुविधाएं उनको देनी चाहिए जो उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक हों।

महोदय, यदि पर कैपिटा आउट-ले पर विचार किया जाए तो 5वीं योजना, 6ठी योजना और 7वीं योजना में जो केन्द्रीय मदद की गई उसके अनुसार 5वीं योजना में जो 1974 बेस लिया गया है वह नान-स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को छोड़कर बिहार का एवरेज 79 आता है जब कि नान-स्पेशल कैटेगरी का 82 है। यह निश्चित रूप से कम है । लेकिन इसके बाद के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 6ठी और 7वीं योजना में वह ज्यादा है । 6ठी योजना में नान-स्पेशल कैटेगरी का 79 आता है और बिहार का 185 आता है । 7वें प्लान में नान स्पेशल कैटेगरी का 291 आता है जब कि बिहार को 301 दिया गया है जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि बिहार की केन्द्र सरकार की तरफ से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की गई सिर्फ 5वें प्लान को छोड़कर । 1980 बेस इयर से किसी प्रकार की कमी नहीं की गई ।

श्रीमती सरला महेश्वरी

इसी प्रकार से जो केन्द्रीय सहायता दी गई ऐन्युअल प्लान में, इस पर हम गौर करें तो नान स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के मुकाबले में बिहार को ज्यादा सहायता दी गई । 1985-86 में यह 36.6 ऐवरेज जो नान स्पेशल कैटेगरी का है उसके मुकाबले बिहार को 64.6 प्रतिशत सेंट्रल असिस्टेंस दी गई । 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 में देखें तो नान स्पेशल कैटेगरी को जितनी सेंट्रल असिस्टेंस दी गई उसके मुकाबले बिहार को ज्यादा दी गई । जब हम 1990-91 के आंकड़े देखते हैं तो नान स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 30.04 दी गई जब कि बिहार को 35.87 दी गई । इसी प्रकार 1991-92 के लिए जो ऐवरेज है वह 32.83 है नान स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो बिहार को दी जाने वाली सहायता 37.11 परसेंट है ।ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि केन्द्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली सहायता में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई । यदि हम 1985 के बाद देखें तो बिहार को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में लगातार बढ़ोत्तरी की गई । इसलिए यह आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है कि केन्द्र सरकार की तरफ से बिहार की उपेक्षा की गई । हम यह स्वीकार करते हैं कि बिहार में बहुत पिछड़ापन है' बिलो पावर्टी लाइन के लोगों की संख्या उड़ीसा के बाद बिहार में सबसे ज्यादा है । हम स्वीकार करते हैं कि वहां मिनरल्स और दूसरे भंडार हैं जिनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है ।

इस राज्य का औद्योगिकीकरण नहीं हो पा रहा है लेकिन हम यह स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं हैं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस राज्य की उपेक्षा की गई । पर इसके अतिरिक्त इस बैकवर्ड स्टेट को आर्थिक पिछड़ेपन की दिशा में आगे लाने के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये जा रहे हैं जब हम इन पर गौर करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि राज्यसरकार की तरफ से राज्य के पिछड़ेपन कोक पूर करने के लिए क्या उपायकियेर जा रहे हैं । मैंने लिटरेसी की बातकही । जो लिटरेसी का रेट है बिहा में नेशनल एवरेज से ज्यादा है । साक्षरता का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या पहल की गई । अच्छा होता माननीयसदस्या जब इसके पिछड़ेपन पर चिंता व्यक्त कर रही थी तो इसकी तरफ भी ध्यान दिलाती । साक्षरता अभिान किस ढंग से चलाया जा रहा है ?कितनी जगह स्कूल, कालिज खोले गये यह बताती । वहां जो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, वहां के मजदूरों की आर्थिक दशा दयनीय होने के साथ साथ शारीरिक दशा दयनीय है, इसके सुधार के लिए कितने अस्पताल खोले गये और उन अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए यह सब बताती तो ज्यादा अच्छा होता । हम बायो-टेक्नोलोजी का कितना उपयोग राज्यों में कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का कितना उपयोग कर रहे हैं, लघु सिंचाई योजना के तहत किसानों की फसल और पैदावर बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं और साथ-साथ केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो विभिन्न मदों में पैसा दिया गया है उसका कितना उपयोग किया गया है जब हम इन सब बातों पर गौर करें तो हम निश्चित रूप से पायेंगे कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो पैसा विभिन्न स्कीमों में दिया गया था उसका सही यूटीलाइजेशन नहीं किया गया । सेवंथ प्लान में आईआरडीपी प्रोग्राम के तहत जो टोटल एलोकेशन हुआ था वह 413.92 करोड़ रुपये बिहार के लिए हुआ था । लेकिन इसका यूटीलाइजेशन जो हुआ वह सिर्फ 412.27 करोड़ रुपये का हुआ । जितनी मदद केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आईआरडीपी प्रोग्राम के तहत दी उस पूरे पैसे का उपयोग बिहार राज्य ने नहीं किया । अगर इसके लिए कोई दोषी है तो वहां की राज्य सरकार दोषी है ।

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

एन०आर०ई०पी० आर०एल०ई०जी०पी० और जवाहर रोजगार योजना के तहत जितना फंड आवंटित किया गया था केन्द्रीय सरकार की तरफ से सेवंथ प्लान में अगर उस पर हम गौर करें तो 1,219.82 करोड़ रुपये दिये गये थे और इसका यूटीलाइजेशन हुआ... (*समय की घंटी*) बड़ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं।..!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude.

**श्री सुरेश पचौरी** : इन आंकड़ों के माध्यम से मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जवाहर रोजगार योजना के तहत 1,219.82 करोड़ रुपये दिये थे और इसका यूटीलाइजेशन वहां की राज्य सरकार ने 1,070.33 करोड़ रुपये का किया। इसी प्रकार से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सेन्ट्रल असिस्टेंट जो 85 से 91-92 तक दिया गया था उसमें भी लगतार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके विपरीत बिहार में क्या हो रहा है? बिहार राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मेरे पास इंडिया टुडे की कापी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 72 सदस्यों के आकार का मंत्रिमंडल गठित किया गया है और उसके लिए 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार को ढोना पड़ रहा है। राज्य के बजट पर 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please conclude. I am calling the next speaker.

**श्री सुरेश पचौरी** : ये सारे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बिहार जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए जो सेन्टर की तरफ से स्कीमें चलाई गई, बैकवर्ड स्टेट को सुधारने के लिए सेन्ट्रल असिस्टेंस स्कीमें चलाई गई उनमें ट्राइबल सब-प्लान चलाई गई, इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण बढ़ाने के लिए पांच ग्रोथ सेन्टर्स खोलने का वहां अगला कार्यक्रम है, ए टी पावर्टी प्रोग्राम चलाया गया लेकिन इस के फंड का यूटीलाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। स्पेशल राइटस प्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया, स्माल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए वहां सेन्ट्रल असिस्टेंस दी जा रही है, स्पेशल एरिया प्रोग्राम चलाया गया, डी०पी०ए०पी०, इसके साथ जो इंसेन्टिव दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा होता हमारी माननीय सदस्य 1989-90 में 90-91 में एनुअल प्लान के तहत नेशनल फंट गवनमेंट के समय जो राशि दी गई थी उसका जिक्र करतीं।

मेरे पास 1985 से अब तक के आंकड़े हैं। जो राशि करोड़ों में दी गई वह 1985 में 851 करोड़ है। लेकिन 1989-90 और 1990-91 में यह... (*व्यवधान*)। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नेशनल फन्ट गवर्नमेंट का जो प्रतिशत है वह एनुअल प्लान में जो असिस्टेंस दी गई वह 0.2 परसेन्ट है और इसके विपरीत जो परसेंटेज है स्टेप अप ओवर प्रिवियस ईयर, वह 33.1 से ले कर 24.7 तक है। यह प्रतिशत कम रहा है। उसकी भी आलोचना अगर माननीय सदस्या करतीं तो अच्छा होता, जब कि कांग्रेस के रिजिम में यह प्रतिशत बढ़ा हुआ रहा। यह प्रतिशत सबसे कम नेशनल फन्ट की गवर्नमेंट के समय रहा। इसलिए यह कहना कदापि उचित नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार के लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से और ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन समुचित प्रयास राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की तरफ से मिले रूप में होना चाहिए। तभी बिहार का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो पाएगा, विकास हो पाएगा।

**PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I represent the State of Bihar in this august House and I am deeply interested in the development of Bihar because development of Bihar is** still-

[Prof. Chandresh P. Thakur]

cal for the development of India. It is a fact that poverty, unemployment and lack of development has characterised Bihar's economy over the last several decades. Interested differences in the development is not unknown in this country but the gap between the national per capita income growth or the rate of growth of the State economy at the national level, and that of Bihar, has been widening unfortunately over the years. Population pressure, and floods and drought together or alternately bring fury and misery in Bihar and the country is familiar with that. Infrastructure is weakest in the country, whether you take the road, the rail, the power, the irrigation system, education and health services; they are all inadequate, and whatever is there, it is at an advanced stage of decay either as a result of neglect or delayed renewal or replacements. Network of the branches of banking and financial institutions is the least in terms of population's share so far as Bihar is concerned, and allocation of financial resources or financial institutions in Bihar has never been kept up at the level promised by the Finance Minister in our discussions with him from time to time. There has been a criminal neglect, whether it is the Central Government or the State Government or both, and the people of Bihar have suffered. I do not care for political persuasion. As a citizen of Bihar, as one who is interested in the development of Bihar, I would like to take a totally non-partisan view. It is true that Bihar Government's utilisation capacity of plan resources allocations has not been sufficient and over the plan period, there has been under-utilisation of the allocated resources. But that does not mean that for all the underdevelopment, inefficiency or indifference of Bihar should be the alibi, because if the country has to develop, the large mass like Bihar cannot b left neglected. It must be noted tha Bihar contributes immensely to th national wealth. So far as natura resources are concerned, it is well-endowed with mineral resources, basic steel, and whether you like it or not, adequate cheap labour is the contribution of Bihar to the rest of the economy of India. But in return, Bihar is not getting sufficiently or adequately so far as its own development is concerned. In fact, for the resources located in Bihar, it has to pay the same price under the freight equalisation as Mrs. Sinha was saying. The Central Government has an onerous responsibility, because if Bihar also gets into the same situation where Assam has come into or where Punjab has come into, or some other restive regions of the country have come into then the country will have to pay a very heavy price. Drag in the development of Bihar is a drag on the development of the country. Keeping this in view, the Government of India should give first priority to the development of Bihar. I would like to invite the attention of the two hon. Ministers—Minister in charge of Economic Affairs and the Minister of Civil Supplies, sitting here—to this. They must take a collective vow that they would ask the question, "Why not this project in Bihar; why not this recovery in Bihar?" rather than finding an *alibi* as to why it should not be in Bihar more so in the north. There is a tendency to say that it should not be in Bihar because it cannot do it or it has not done it. This should be reversed. There is a gap between the national scene and the Bihar scene. In order to remove this gap and accelerate the development, there should be a proactive and an innovative strategy. Unless the collective will the the Government of India and the Government of Bihar is put together, our country will suffer. I have to make a few concrete suggestions. Firstly, there should be a substantial step-up in the investment on the basic infrastructure so far as the State of Bihar is con-

cerned. By infrastructure, I mean, irrigation facilities, power, road, health and medical facilities. The allocation to sectors other than the coal and steel sectors by the Central Government has been nothing in the last several decades. This is very unfortunate. I would like to suggest that when allocation is made to the State of Bihar, whatever be the total investment without considering the allocation to the coal and steel sectors, Bihar should get this share on a *per capita* basis. Otherwise, the development cannot be accelerated. Particularly, in the north Bihar where the intensity of population pressure is very high, the situation is very bad. Perennial rivers are there. They are in floods. In order to provide a powerful growth centre in north Bihar a metal—based large engineering industry should be established and the existing units should be substantially expanded like for example, Bharat Wagon. It is a surplus generating unit and it is an efficiently managed unit among the public enterprises. They are willing to expand. So, the Central Government should provide all the resources and support for its expansion. If this is developed, its ancillary units all over the State would develop.

It is unfortunate that the licences held by the banks issued by the Reserve Bank of India have not been implemented so far as the bank branches are concerned. This gap must be overcome expeditiously. The existing public sector unit, the Bokaro Steel Plant, is a surplus-generating unit. When it comes to expansion, it has been pushed to the back. The resources generated by the Bokaro are being diverted. I am not against modernisation and expansion of the steel plants at Rourkela or Durgapur. But the Bokaro Steel Plant must be expanded and the growth of its ancillary units must be accelerated on a healthy basis.

The Government has an impressive programme for food-processing industries. Bihar is one of the agricultural States. A variety of fruits, vegetables and agricultural products are being grown there. So allocation to food-processing industries in different parts of Bihar must be made on a priority basis resulting in value-added gains to agricultural producers and creating employment opportunities for the people of Bihar.

Bihar being one of the places of tourist importance, lack of infrastructural facilities has created a tremendous handicap to the tourists visiting that State. The allocation of resources to improve the infrastructural facilities for tourists is not made. I would like to urge upon the Government to take a serious note of this. This programme would generate both income to the Government and employment opportunities to the people. A time-bound programme should be drawn up to implement it. The Minister of Planning is sitting here I would, particularly, draw the attention of the Ministry of Planning and the Planning Commission. They should set up a special team, either of Members of Parliament or of civil servants, to go and examine, on an expeditious basis, what is ailing the development of Bihar and which are the priority areas which should be taken up for action.

In this connection, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to remind that in June, 1989, the late Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi while delivering the valedictory address at a two-day seminar on industrialisation in Bihar, declared that a special cell would be created in his Secretariat, i.e., the Prime Minister's Secretariat, to monitor industrialisation and other development programmes in Bihar. I know that Mr. B. G. Deshmukh, the Principal Secretary to the Prime Minister then, was co-ordinating that. I would like the same process to be revived and programmes implemented on a time-bound basis.

Shri Rajiv Gandhi also said that the people of Bihar should be self-dep-

[Prof. Chandresh P. Thakur]

endent, not merely looking to others for help. I would like to suggest that the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Industry and the Banking Department must take necessary steps for development of indigenous entrepreneurial capability and infrastructural support. Then, things would move fast.

In the end, I would like to say that, unfortunately, Bihar is being taken over by the restive elements. The youth of Bihar is restive. Criminal and anti-social elements have taken charge of the situation and the State Administration has lost total interest in the development process. It is busy in the political process.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: The present Government?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I mean, the present State Administration.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Do you mean to say that Bihar has become backward in the last one-and-a-half years?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: It is a cumulative process. They have accelerated the process. Sir, let me put on record that the Janata Dal has got the maximum number of Members of Parliament from Bihar, but they have done precious little for the development of Bihar. It is a criminal neglect. It is an act of ingratitude to the people of Bihar who have reposed faith in them. They have got in return nothing, not even a gesture. From that point of view, Bihar has suffered lately much more miserably.

Under these circumstances, the warning that Shrimati Kamla Sinha has given must be taken note of. I hope she was not making a political point. There are disturbing symptoms in Bihar and these are because of lack of development. Economic opportunities are few and far between. It is not on par with the rest of the country. In fact, it is in the reverse gear. If this is not corrected, the country will have to pay a very heavy price. We hope that under the new Congress Government, things would move in a different direction, much more speedily and with a rich agenda of development programmes.

Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity. I also thank Mr. Satya Prakash Malaviya for giving me the floor ahead of him.

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश पचौरी जी, प्रो० ठाकुर जी तथा अन्य माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने बहुत ध्यान से सुना । मैं समझता हूं कि श्रीमती कमला सिन्हा जी के प्रस्ताव की जो प्रथम तीन पंक्तियां हैं कि यह सभा इस तथ्य पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है कि उर्वर कृषि भूमि, यथेष्ट जल संसाधन और अतुलनीय खनिज सम्पदा होने के बावजूद बिहार राज्य देश के सर्वाधिक निर्धन राज्यों में से एक है, यह प्रस्ताव की प्रथम तीन पंक्तियों हैं, जिनको मैंने अभी पढ़ा है । इससे किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता । यह सही है कि बिहार देश के जो अन्य प्रदेश हैं उन में उत्तर प्रदेश के बाद सब से अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है । बिहार में, जैसे कि श्रीमती कमला सिन्हा जी ने विस्तार से चर्चा की है कि खनिज पदार्थ वहां पर बहुतायत मात्रा में मिलते हैं । निरक्षरता के संबंध में नीचे से अगर चलें तो टॉप पर बिहार है । भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है जैसे कि हमारे संविधान में कहा गया है ।

जब बिहार की उन्नति होगी तभी भारत की भी उन्नति होगी और इस दृष्टि से हमको इसे देखना चाहिए । बिहार में आज चाहे जिस स्तर पर गिरावट हो लेकिन हम डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम को भूल नहीं सकते जो इस देश के दो बार राष्ट्रपति थे और उनका जो सीधा साधा जीवन था, आचरण था उससे आज हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि दो दो बार राजेन्द्र बाबू इस देश के राष्ट्रपति रहे लेकिन राष्ट्रपति के पद से पद मुक्त जब हुए तो उनके पास पटना में रहने के लिए अपना कोई मकान

नहीं था और अपने आवास के लिए उनको सदाकत आश्रम में शरण लेनी पड़ी । इसी तरीके से बिहार में लोक नायक जय प्रकाश नारायण का उदाहरण है । बाबू कुवर सिंह की चर्चा की गयी जो अंग्रेजों के जमाने में एक अग्रणी सिपाही थे । वे नदियों के जरिये चलकर आजमगढ़ से बिहार आये और अंग्रेजों से मुकाबला किया । राष्ट्रकवि रामधारी सिंह "दिनकर" भी वहीं पर हुए हैं। इसलिए बिहार की जो आज गरीबी है उसको देखकर सारे देशवासियों को आगे आना चाहिए चाहे वे सत्ता में हों चाहे सत्ता के बाहर, कि किस तरीके से बिहार काफ्जो आर्थिक पिछड़ापन है, गरीबी है, निरक्षरता है उसको हम दूर कर सकते हैं।

जो 1991 का सेंसस है, मर्दुमशुमारी है उसके हिसाब से बिहार की जनसख्या 8,63,08,853 के करीब है । मैं उद्धृत करना चाहता हू । यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिपोर्ट है हमारे पास, 1985–86 की, इसमें वहां की लिट्रेसी के बारे में और विशेषकर महिलाओं की लिट्रेसी के बारे में चर्चा की गयी है । इसमें यह कहा गया है :

> "On the other hand, as before, Bihar remained at the bottom with women enrolment only 14.4 per cent of its total enrolment in 1985-86."

इसमें फिर बाद में एक परिशिष्ट भी है जिसमें यह बतलाया गया है कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है इसमें महिलाओं में साक्षरता 1981–82 में 14.2 प्रतिशत थी, 1982–83 में 14.7 प्रतिशत थी, 1983–84 में घट गयी और हो गयी 13.6 प्रतिशत, फिर 1984–85 में 14.4 प्रतिशत और 1985–1986 में 14.5 प्रतिशत । इन पांच वर्षों की चर्चा मैंने इसलिए की कि 1981–82 में इसकी साक्षरता का जो प्रतिशत था वह केवल 14.2 प्रतिशत था और 1986 तक बढ़ते बढ़ते केवल 14.5 प्रतिशत हुआ।

इसके बाद अभी जो डाइरेक्ट्रेट आफ एडल्ट एजूकेशन है इनकी ओर साक्षरता मिशन के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित की गयी है और उसमें भी बिहार के बारे में चर्चा की गयी है जो 1991 के सेंसस के आधार पर लेटेस्ट है इसमें यह कहा गया है : Its heading is "States and Union Territories arranged in descending order of literacy rate among persons 1991."

हमारे देश में शायद कुल 32 राज्य हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, इस सूची में बिहार की जो साक्षरता दिखायी गयी है, लिट्रेसी रेट वह 38.54 प्रतिशत है । इसमें जम्मू और काश्मीर का नाम नहीं है क्योंकि उनके आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं थे 1991 के सेंसस में । लेकिन इसमें जो 31 राज्यों की चर्चा की गयी है इसमें बिहार का नाम सबसे नीचे है यानी आज भी बिहार में जो साक्षरता का रेट है सारे देश में सबसे नीचे है और इसके बाद इसमें महिलाओं के संबध में चर्चा की गयी है । 1991 में बिहार में जो कुल जनसख्या है, आज की तारीख में केवल उस जनसख्या का 38.54 प्रतिशत साक्षर है जिसमें पुरुषों का प्रतिशत है 52.61 और महिलाओं का 23.10।

5.00 P.M.

डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने अभी जिक्र किया है कि बिहार में आज तक भी वहां पर कोई सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय वहां पर नहीं है । अभी कल ही हमारा एक प्रश्न था कि बिहार में कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, सरकार के पास अभी आंकड़ा केवल 1987–88 तक का उपलब्ध है । मेरा कल ही का अतारांकित प्रश्न सख्या 614 था, जिसमें यह कहा गया है कि हाल ही के वर्ष 1987–88 में जिसकी सूचना उपलब्ध है, बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की सख्या 336.54 लाख थी । इसके मायने यह कि 3 करोड़ 36 लाख और 54 हजार है और मेरे पास पापुलेशन का इसी सरकार का एक दूसरा आंकड़ा है उसके हिसाब से 49.5 प्रतिशत आज भी बिहार में ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं । इसलिए मैं श्रीमती कमला सिन्हा के प्रति आभार प्रकट करता हू, उनको बधाई तो नहीं देता कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक प्रस्ताव आज यहां पर प्रस्तुत किया और उस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है । आज बिहार में उद्योग के नाम पर अगर यह कहा जाए कि बिल्कुल शून्यता है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी । क्योंकि शायद टाटा, डिलको या बोकारो

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

स्टील प्लांट या जो रांची का एक हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन है, यह 4-5 उपक्रमों को छोड़कर के बिहार में उद्योग के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। दूसरी ओर बिहार में जहां तक रेल की लाइनें हैं, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां कि रेल की लाईन बहुत ही कम मात्रा में लंबाई को ले करके वहां पर उपलब्ध है और इसके अलावा वहां आज जो कुछ भी रेलवे है कम से कम बिहार प्रदेश में सब की गति बहुत ही धीमी है। बहुत दिन से एक बात चल रही है छतौनी की एक पुल की बात है। शायद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने या ललित नारायण मिश्र जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन इसका कार्य 7 जनवरी, 1990 को प्रारम्भ हुआ और करीब-करीब डेढ़ साल हो गया है, लेकिन भारत सरकार का यह कहना है कि अभी, आधार-शिला शायद 1974 में इसकी रखी गई थी, लेकिन कार्य गत वर्ष शुरू हुआ। इससे यह है कि अगर यह पुल बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार की दूरी काफी कम हो जाएगी, लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और ठीक प्रकार से व्यापार करने में सुविधा होगी। लेकिन भारत सरकार का उत्तर यह है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों द्वारा अभी तक 1990-91 तथा 1991-92 के लिए लागत के अपने हिस्से का भुगतान न किए जाने के कारण कार्य में बहुत ही विलम्ब हो रहा है। इसका पूरा होना सब भागीदारों द्वारा अपने हिस्से का भुगतान कर दिए जाने पर ही निर्भर होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहें उत्तर प्रदेश या बिहार हो, उनकी आर्थिक स्थिति आज ऐसी नहीं है, यह जो सारी योजना है सड़क-पुल सहित 159 करोड़ रुपए की है। भारत सरकार ने खुद कहा है कि यह अपने अपने भाग जो अदा नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, इसलिए यह पुल बन नहीं पा रहा है, बनने में देरी हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि भारत सरकार को इस संबंध में गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह प्रदेश का जो अपना हिस्सा है उसको वह दे पायें, न दें पायें, लेकिन उस पुल को बनाने का काम जल्दी ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी गरीबी दूर होगी। वहां का भी आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा और बिहार का भी आर्थिक पिछड़ापन जो है इसको दूर करने में सहायता मिलेगी।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश में एक श्री विश्वनाथ जी गहमरी थे, उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गरीबी है उसका चित्रण लोक सभा में किया था। श्री जवाहर लाल नेहरू उस वक्त जीवित थे, वह प्रधान मंत्री थे उस समय और जब उन्होंने लोक सभा में वहां की गरीबी का चित्रण किया तो उससे पंडित जी बहुत द्रवित हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक आयोग की स्थापना की। तो मेरा यह एक सुझाव है कि आज यहां पर जो विचार-विमर्श हो रहा है, पहले भी हुआ होगा लेकिन इस बारे में कोई विवाद या मतभेद नहीं हैं कि बिहार हमारे देश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है, शिक्षा के स्तर पर भी और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी। इसलिए वहां की गरीबी को दूर करने के लिए, वहां साक्षरता लाने के लिए, सारे बिहार की उन्नति के लिए मेरा सुझाव है कि जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में श्री जवाहर लाल नेहरू के समय में एक पटेल आयोग की स्थापना की गयी थी और उसका कार्यक्षेत्र यह था कि सारा परीक्षण कर वह भारत सरकार को सुझाव देगा। इस तरह के एक आयोग की स्थापना भारत सरकार को तुरंत करनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मंत्री जी खुद कुछ घोषणा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

महोदय, श्रीमती कमला सिन्हा ने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि बिहार की जो उपेक्षा है, वहां की जो हालत है उसको इस सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इससे वहां पर एक जन आक्रोश है। जैसे वहां पर एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो अपनी

मांग रख रहा है । एक संस्था आय०पी० एफ० है इसके अलावा बिहार के कुछ क्षेत्रों में नक्सलाइट्स का कफोजोर है और विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा की घटनायें हुआ करती हैं । तो बिहार के लोगों को इस बात का संतोष होना चाहिए कि जो केंद्र की सरकार है वह हमारे साथ उपेक्षा का व्यवहार नहीं कर रही है । इसलिए श्रीमती कमला सिन्हा जी ने जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उस ओर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

इसके साथ ही मान्यवर वहां पर कटिहार में एक जूट मिल थी । वह मिल आजकल बंद पड़ी हुई है । वह सन् 1982 से बन्द पड़ी हुई है । वहां 18 सौ कर्मचारी काम कर रहे थे । इस बात को लेकर बिहार के लोकसभा के सदस्य श्री ओराज 10-15 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे । इस बारे में वस्त्र मंत्री श्री अशोक गहलोत से भी मिले थे । उनकी यह मांग है कि टिकहर जूट मिल को चालू किया जाए और 18 सौ परिवार के लोग जोकि बेरोजगार हो गये हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाय । इसलिए मैं मांग करता हूं कटिहार जूट मिल को चालू किया जाए । मैं एक मांग और रखूंगा कि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का सम्मान होगा तो वह सारे देश का सम्मान होगा । हमारे बहुत से राजनेता हैं जिनके सम्मान में डाक टिकट निकाले गए हैं । मैं इस संबंध में काफी दिनों से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया हूं । इसलिए आज मैं आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के संबंधित मंत्री तक हमारी बात को पहुंचाया जाए कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के सम्मान में भारत सरकार को बहुत शीघ्र डाक स्मारक टिकिट निकालना चाहिए । इस बारे में विभागीय मंत्री श्री पायलट का कहना है कि उसे एक समिति के सामने रखा जाएगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका सम्मान कर के हम केवल बिहार का ही नहीं वरन पूरे देश का सम्मान करेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमती कमला सिन्हा के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि श्री इंद्रराज भारद्वाज जी शायद उत्तर देंगे तो वह जरूर इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि भारत सरकार निकट भविष्य में ही ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि बिहार की गरीबी, पिछड़ापन और वहां की निरक्षरता दूर होगी ।

**श्री भंवर लाल पंवार** (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती कमला सिन्हा जी के संकल्प के संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा चर्चा के दौरान जो आंकड़े दिए गए हैं मैं उन्हें वापिस दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इस संबंध में इस संकल्प के लिए केंद्रीय सरकार के बारे में जो बात कही गयी है, उससे अपने भिन्न विचार रखना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की धरती को नमन करता हूं । उस धरती ने हमारे राष्ट्र को सर्वोपरि नेता दिए हैं । प्रारंभ में, डा० राजेन्द्र प्रसाद भारत रत्न जहां से आए और उनके कार्यकाल में केंद्र पर उनका पूरा अस्तित्व छाया रहा । और उसके बाद बाबू जगजीवन राम जी उसी धरती से यहां आए, जिन्होंने हिन्दुस्तान का नेतृत्व किया । इस संदर्भ में उस धरती से स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख जो हो चुका है, उन व्यक्तियों के तो नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणीय रहे । आध्यात्मिक दृष्टि से भी वहां से जो संत आए उन्होंने चरित्र-निर्माण के लिए भारत की संस्कृति में बहुत अधिक योगदान दिया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से प्रकृति ने बिहार को जल-संपदा और खनिज संपदा भरपूर दे रखी है । फिर क्या कारण है कि वह अभी तक इतना पिछड़ा रहा है ? हिन्दुस्तान की पूरी धरती 3,287.3 किलोमीटर है, जिसमें बिहार का क्षेत्रफल 173.9 किलोमीटर है । वहां की आबादी 359.3 लाख है,

[श्री भंवर लाल पंवार]

जो कि उस धरती पर बहुत ही बोझ है। यह उस धरती का प्रताप है कि इतना बोझ सह रही है और अपने आपको उन्नत नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में मैं यहां यह उल्लेख करना आवश्यक समझूंगा कि हम देखें कि वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री जिस रूप में अपने परिवार को चला रहे हैं और जो राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है—परिवार नियोजन की, उस ओर वह स्वयं अग्रणीय नहीं हो पा रहे हैं। तो उस धरती पर बोझ बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा नहीं। मैं इस सदन के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई प्रजातंत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधि आए, वह वर्तमान परिवार नियोजन की बात को पूरा अमल में लाए। अगर उस पर अमल न करे तो, जनप्रतिनिधि कानून में भी एक ऐसा कानून होना चाहिए जिससे उसके लिए रुकावट पैदा हो कि, ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में वहां किसी मुख्य स्थान पर न आने दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो पिछड़ेपन का मुख्य कारण है वह है प्रकृति का प्रकोप। हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष में प्रत्येक राज्य के लिए जब प्लानिंग होती है तो हर प्रांत के मुख्यमंत्री प्लानिंग मिनिस्टर के पास आकर अपना-अपना शेयर मांगते हैं। अब प्लानिंग मिनिस्टर, केंद्र उनकी आवश्यकता के अनुसार धन आवंटित नहीं करता, यह मैं मान नहीं सकता। फिर, वहां सारी प्रकृति की बातों को भी देखा जाता है। ऐसा न हो कि जितना धन वहां दिया जाए, वह धन वहां बह जाए; जैसा कि प्रकृति ने प्रकोप बिहार पर कर रखा है। आए साल वहां बाढ़ से पूरी तो सड़कें नष्ट हो जाती हैं, पूरी फसल नष्ट हो जाती है और उसके कारण भी वह पिछड़ा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यहां सदन में एक तारांकित प्रश्न था, प्रश्न संख्या 167, उसके ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि गंगा नदी के जल को कावेरी में अंतरित करने के संबंध में डा० के० एल० राव के प्रस्ताव की सरकार ने जांच करके उसको इकोनोमी कली वाइबल बनाकर उस पर अमल नहीं किया। अगर प्रारंभ से, अपनी स्वतंत्रता के बाद से उस पर धीरे-धीरे अमल किया जाता तो बिहार उससे बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त कर लेता।

अब इस तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो बात कही गई है कि 17 नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की कल्पना की गई है और उस पर अमल किया जाएगा। यही एक ऐसी बात है जिस पर कि केंद्रीय सरकार ध्यान देकर वहां जल का इस प्रकार से वितरण कर दे कि जिससे बिहार बहुत प्रभावित न हो नुकसान के लिए और अन्य राज्य उससे लाभ पा सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है कि बिहार जल के कारण वीरान हो रहा है और मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान जल के अभाव में वीरान है। तो इसलिए इस संकल्प में जो केंद्रीय सरकार पर हम भार डालना चाहते हैं वह मुख्य भार यह केंद्रीय सरकार अगर अपने ऊपर झेल ले तो वह पानी के कारण वीरान नहीं होगा और राजस्थान पानी के अभाव में तड़पेगा नहीं।

दूसरे, बिहार के पिछड़ेपन का जो कारण अब तक हम देख रहे हैं कि वहां जनसंख्या का जो वितरण है, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो संख्या है—बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट लगभग सवा करोड़ हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लगभग 60 लाख हैं और इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग भी बिहार में बहुत ज्यादा हैं। तो यह जो पिछड़ेपन का कारण है, उनको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, जैसा मालवीय जी ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जो अभी तक वहां बिहार का हाल है, वह केवल इस पिछड़े वर्ग के, शैड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अधिक जनसंख्या के कारण ही बिहार का पिछड़ापन है। जो वहां प्रोडक्शन होता है, उसकी कारण जो भी वहां धन का उपार्जन होता

है, उसका सही वितरण इसी कारण नहीं हो पा रहा है । अगर धन का सही वितरण होने लग जाए उन लोगों को भी व उनकी मजदूरी के कारण जो उनका योग है उपार्जन में, वह उनको मिल जाए तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी । यह काम राज्य सरकार के ऊपर आता है और राज्य सरकार आज तक इस ओर ध्यान पूरा नहीं दे पा रही है । यही कारण है कि वहां अभी तक इतनी भारी गरीबी है ।

महोदय, बिहार में जनवरी, 1986 से आज तक 25 मुख्य मंत्री हुए हैं और 25 मुख्य मंत्रियों के होने के बाद भी जो-जो सरकारें वहां रही हैं--राज्य सरकारें, वे सब और मैं तो यह सोचता हूं कि 1968 से 1970 का समय और 1977 से 1990 के अंत तक के समय के अंदर वहां ज्यादा अत्याचार हुए हैं और वर्तमान में जो हुआ है , अभी इसी 1991 का इलैक्शन में इलैक्शन आयुक्त ने यह बात कही है कि वहां केवल आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं है । केवल जनता ही नहीं, अधिकारी वर्ग भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं पा रहे हैं । उनको यह कहा जा रहा है कि यदि आप हम जैसा कहें, वैसा करोगे तो आप अपने आपको सुरक्षित पाओगे । ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI KAMLA SINHA: I am on a point of order, Sir. I object to what the hon. Member said.

किसी अधिकारी ने यह बात नहीं कही कि हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं । चुनाव आयोग ने बिहार के साथ चुनाव के दरमियान जो कार्रवाई की, उस पर बिहार की सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास बार-बार आपत्ति की है । चुनाव आयुक्त की चर्चा यहां न की जाए, चुनाव आयुक्त के ऊपर हम लोग महाभियोग इसलिए ला रहे हैं । We are going to impeach him for that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. MAGEN SAIKIA): Please carry on.

**श्री भंवर लाल पंवार :** उपसभाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य हैं, जो सत्य है, वह रिकार्ड पर आएगा और उसको नकारने के लिए तो उसका प्रतिकार ही अगर रिकार्ड से होता है, तो होगा ।

पूरे देश में यह प्रचार चला, यह हुआ और बिहार में प्रजातांत्रिक प्रणाली को जो धक्का लगा वह बेमिसाल है आज तक की प्रजातांत्रिक प्रणाली के कारण । महोदय, बिहार के लोगों को वहां पर काम करने की और काम का अवसर देने की राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है वह पूरी नहीं करने के कारण ही पूरे हिन्दुस्तान में बिहारी बाहर-बाहर भटक रहे हैं । यह स्वयं एक ऐसी मिसाल है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से नहीं निभा रही है , वरना क्यों एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग अपने जीवकोपार्जन के लिए जायें ? राजस्थान का क्षेत्रफल, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां का क्षेत्रफल 342 एकड किलोमीटर है और जनसंख्या भी 3 करोड 42 लाख है । लेकिन बिहार की भूमि तो 173.9 लाख है --(**समय की घंटी**)-- और उस पर जो जनसंख्या का भार है वह 6 करोड 99 लाख है और इसके कारण उस भूमि पर जो भार है वह इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट को उसमें और अधिक सहयोग देने की जरूरत है, जनता को राहत पहुंचाने की जरूरत है ।

मैं माननीया कमला सिन्हा जी के प्रस्ताव का समर्थन इस बात तक करते हुए कि बिहार के गरीब लोगों को वहां पर इस प्रकार राहत पहुंचायी जाए, उनको रहने के लिए स्थान दिया जाए, --(**समय की घंटी**)-- उनको रोजगार के अच्छे अवसर दिए जायें, और उसके बाद केंद्र सरकार उस जल का इस प्रकार से नियंत्रण करे कि वहां पर विनाश न हो, तभी यह काम पूरा हो पाएगा । धन्यवाद ।

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, as time

is short I will take only three minutes. Though the Resolution moved by Shrimati Kamla Sinha is related to the State of Bihar, the main objective behind this Resolution is development of the backward regions in the country. I hail from Rayalaseema area of Andhra Pradesh. Everybody knows that Rayalaseema area is one of the most backward areas in the entire country. So, I am participating in this discussion.

Sir, the objective of the Five Year Plans is a balanced growth of all the regions in the country; unfortunately after seven Five Year Plans this regional disparity has increased more than what it was in 1947. The reason for this is in the Plan outlays while giving Central assistance our plamners are allocating more funds to the developed States. They are investing more funds on the developed States and on the developed areas because they can get more returns and quick returns from those developed regions; that is why they are investing. From the underdeveloped areas they are getting less. This is the main reason for this regional disparity. If we see the Plan Outlay, the eight developed States are getting 50 per cent share and the remaining States are getting the remaining 50 per cent share. In an egalitarian society it is the responsibility of the Government to remove this regional disparity and save the country from disintegration. In this context I would like to submit some suggestions. First is the Government should constitute a national committee for development of backward areas. First of all, the backward areas should be identified in the country. For this, a committee should be constituted. The second suggestion is there should be a special areas cell. Then you should allocate special funds every year, at least Rs. 2,000/- crores, for development of these backward areas. With these suggestions, I conclude.

**श्री रजनी रंजन साहू** (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तुलसी रेड्डी जी को धन्यवाद देना हूं कि उन्होंने बिहार की समस्या को देखते हुए बहुत जल्दी अपनी बात खत्म की और मुझे अवसर दिया है । महोदय, मैं श्रीमती कमला सिन्हा जी के रेजोल्यूशन से पूर्णतया सहमत नहीं हूं क्योंकि जब आप इस रेजोल्यूशन को दो हिस्सों में बांटेंगे तो अंत में यह लिखा है कि —

"...in that State and, therefore, urges upon Government to take necessary steps forthwith to undo the consistent neglect and economic exploitation of the people of Bihar."

इसके दो हिस्से हैं— 'consistent neglect' and 'Government to take necessary steps forthwith

जहां तक प्रश्न है कि 'Government has to take necessary steps forthwith'

मैं इससे सहमत हूं । केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को मिलकर यह बात तय करनी चाहिए कि बिहार का विकास कैसे हो । जहां तक "consistent neglect and economic exploitation of the people of Bihar" का सवाल है, इसमें मैं असहमत हूं । कंसिस्टेंट नैग्लेक्ट कभी नहीं हुआ है । बिहार की भूमि के बारे में जो केंद्रीय सरकार का रूख शुरू से रहा है, वह बहुत सराहनीय रहा है ।

**श्रीमती कमला सिन्हा** : साहू जी, बिहार के लोग इस बात को नोट करेंगे ।

**श्री रजनी रंजन साहू** : कमला सिन्हा जी, मैं बताना चाहता हूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आवश्यक इन्फास्ट्रक्चर बिहार को चाहिए था जैसे रोड और बिजली वह मिला । मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार को पावर के लिए जो हिस्सा मिलना चाहिए था वह लगभग 8 प्रतिशत है

[श्री रजनी रंजन साहू]

महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आल इंडिया इन्वेस्टमेंट 260 करोड है जब कि बिहार का 20.53 करोड दिया है। बिहार की पापुलेशन 10 परसेंट है, उस हिसाब से प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 7.90 परसेंट बिहार में पावर के जैनेरेटर के लिए दिया गया था।

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Give some time to the Minister.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: The Minister will say something after I finish.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): Are you going to finish? You will continue in the next Session.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: We will continue in the next Session.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You please conclude.

श्री रजनी रंजन साहू : उपसभाध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं यह कहा रहा था कि बिहार को प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि पावर इन्फास्ट्रक्चर के लिए मिलनी चाहिए थी वह मिली। जब 1967 के बाद संविद सरकार का प्रादुर्भाव हुआ उस प्रदेश में, तब से विकास का काम वहां ठप्प पड़ गया। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि तभी से सामाजिक विषमता का बीजारोपण उस प्रांत में हुआ और वह सामाजिक विषमता और सामाजिक तनाव आज तक चल रहा है। मैं आपसे और आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार से कहूंगा कि वह राज्य सरकार के ऊपर इस बात का दबाव डाले कि उस प्रदेश में जो सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां का पिछड़ापन और भी बढ़ रहा है, वह सबसे पहले उसको दूर करे। महोदय, ला एंड आर्डर का विषय राज्य सरकार के पास है और वहां फिरौती का धंधा जोरों पर है, वहां लूटमार होती है। वहां तब तक कोई औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है जब तक वहां से सामाजिक तनाव दूर न हो जायें। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Minister, you will get only one-and-a-half minutes.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Mr Vice-Chairman, Sir, I have listened with great interest to all the speeches made by hon. Members, specially the mover of this Resolution. She has put her case very ably making very forceful points about the matter of which we are all concerned. Bihar is relatively poor. It is the view of every Member and when we look at Bihar nobody can deny the tremendous culture, heritage, the revolutionary history, participation in freedom movement of the people of Bihar, their rich mineral, their rivers and such magnificent people. There is no dispute about it and there is further no dispute that we must have proper and equitable distribution of the resources of this country and there should be allround development of the population of this country. But you will appreciate that this is a vast country, a country of several States, several regions. When we achieved freedom, there was an ocean of poverty with only a few islands of richness in this country. Therefore, planned development which was started after the freedom movement is the only way to fight poverty. Poverty is one enemy which has to be fought by all States, by all people, by the resources available with us. Bihar has a rich heritage. It is rich in many things. Yet why is Bihar backward? That is a matter which is of grave concern to us. Mrs. Sinha has demonstrated the situation by figures. There is no dispute about it

and we are all concerned. But I would urge upon her, through you, that there is a system by which we distribute the financial cake we have with us. There is a formula which we have adopted. Not only this Government, but all successive Governments have been following this. The formula provides for 55 per cent on the basis of population. Earlier it was 60 per cent. That is one. Second, per capita income. The existing formula provides 20 per cent for this as earlier. The distance between the highest per capita income and the per capita income of the concerned State was not considered earlier. At the last meeting of the National Development Council it was made 5 per cent. Tax effort for 10 per cent has now been removed. Fiscal management, 5 per cent, has been introduced. Special problems 15 per cent as against 10 per cent earlier. That is how we distribute the cake of hundred rupees percentage-wise. Now, this matter of allocation has been discussed. It is not that the Central Government distributes money arbitrarily. The Central Government, the Planning Commission, they discuss in full strength...

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: I would like to know from the honourable Minister about the late Prime Minister's package of Bihar which he had given as far back as 16th June, 1989. What is the position of that package? If he is talking about the cake which he has got, what has happen to the package which was been given, I do not know whether he has got this figure with him. If he does not have...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please don't interrupt.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I am giving the basics, honourable Members must know. What package you are talking about, I konw. But we must remember the basics. A plea was made by the honourable Member...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): What is this 15 per cent, 10 per cent? Of what?

SHRI H. R. BHARDWAJ: On the basis of the population...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please don't interrupt.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: The Minister is speaking in order to make us understand and if we do not understand what he says, we are legitimately entitled to ask.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I cannot improve his understanding...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: What do you mean? You make a cryptic statement and then say Members don't understand! You can't say that. You are giving figures of percentages. Percentage of what?

*(Interruptions)*

SHRI H. R. BHARDWAJ: If you have any ambiguity I will repeat all over again. Out of hundred rupees 55 is given on the basis of the population of the State. The more the population, the more the allocation.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Which hundred rupees? Is it out of the national income?...

*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Salaria, please don't interrupt.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, he should be educated enough to understand how the Central assistance is given to the States. I cannot educate him on that. The Central Government cannot act arbitrarily in

this case. It has been alleged that the Central Government gives a stepmotherly treatment with regard to some States. But that is not the case. The Central Government cannot act arbitrarily because the whole thing is discussed in the Planning Commission and again we have the National Development Council. All the States participate in these discussions. I have the minutes of the last meeting of the National Development Council. I have gone through these minutes carefully. I have noted down as to what was discussed by the two former Prime Ministers with the Chief Ministers. The Chief Ministers have been drawn our attention to the difficulties they are facing. But the question is about the money. From where should the Centre collect funds to assist the States? We will have to arrive at a formula... (*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Where does the Centre get the money from? The money comes from the States. What is given to the States is less than what is collected from them.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The question is one of finding an alternative... (*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: We would like to know what the alternative is. The formula is not from the Gita. This is a formula which has been created by you. The formula by which you have created this Central fund is itself wrong.

SHRI H. R. BHARDWAJ: There is nothing wrong in it.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: My friend, you are an advocate and you must understand.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please, Mr. Salaria don't interrupt. You have made your point and now let him speak.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The Money comes from the whole country. This is discussed in the National Development Council. The National Development Council consists of the Chief Ministers of the States. The Chief Ministers have discussed the matter of Central assistance in the National Development Council and they have complained that the existing formula is not working satisfactorily. They have suggested alternatives and these are being examined. The National Development Council is the proper forum where these things are discussed. The backward States have complained that the Centre is not giving them enough assistance and that it is discriminatory. For example, about freight equalisation policy of the Government, the State have complained and we are examining it. In a country like ours, we can solve problems only through discussions. The Central Government cannot act arbitrarily nor can the State Government do it. This matter is pending discussion in the National Development Council. The hon. Prime Minister has made a policy statement recently. He has categorically stated that to fight poverty we will have to unite. There is no question of functioning in isolation either by the States or the Centre. This menace of poverty needs to be fought unitedly. It will not be a proper approach if we are to say that we should be disunited to fight poverty. In the National Development Council meeting, I had discussions with the Chief Minister of Bihar. We discussed the royalty on coal and the matter was sorted out. If the Chief Minister wants to take credit for it, he can take that credit.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The question is one of finding an alternative... (*Interruptions*)...

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: We would like to know what the alternative is. The formula is not from the Gita. This is a formula

[Shri H. R. Bhardwaj]

which has been created by you. The formula by which you have created this Central fund is itself wrong.

SHRI H. R. BHARDWAJ: There is nothing wrong in it.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: My friend, you are an advocate and you must understand.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please, Mr. Salaria don't interrupt. You have made your point and now let him speak.

SHRI H. R. BHARDWAJ: The money comes from the whole country. This is discussed in the National Development Council. The National Development Council consists of the Chief Ministers of the States. The Chief Ministers have discussed the matter of Central assistance in the National Development Council and they have complained that the existing formula is not working satisfactorily. They have suggested alternatives and these are being examined. The National Development Council is the proper forum where these things are discussed. The backward States have complained that the Centre is not giving them enough assistance and that it is discriminatory. For example, about freight equalisation policy of the Government, the States have complained and we are examining it. In a country like ours, we can solve problems only through discussions. The Central Government cannot act arbitrarily nor the State Government can do it. This matter is pending discussion in the National Development Council. The hon. Prime Minister has made a policy statement recently. He has categorically stated that to fight poverty we will have to unite. There is no question of functioning in isolation either by the States or the Centre. This menace of poverty needs to be fought unitedly. It will not be a proper approach if we are to say that we will be disunited to fight poverty. In the National Development Council meeting, I had discussions with the Chief Minister of Bihar. We discussed the royalty on coal and the matter was sorted out. If the Chief Minister wants to take credit for it, he can take that credit. But there was no unwillingness on the part of the Centre to extend its help to the States. All the Chief Ministers are invited to discuss their special problems. Through you, Sir, I want to convey the policy of the Government. There is absolutely no deliberate neglect of any State because powerful States mean a powerful Centre and we do not want to neglect any State. But the Centre's financial cake is limited and you cannot extend it disproportionately. That has to be distributed among all the countrymen, among all the States, of the country.

Sir, I want to say a few things more. There is a Constitutional scheme under which the Centre and the States work. If there is any tension on any issue, that has to be sorted out. I am saying this because the question of Centre-State relations was raised. That also is a matter of discussion. The Inter-State Council has been constituted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Mr. Minister, you have to be brief because there is constraint on time. You need not repeat the points.

SHRI V. NARAYANASAMY: How can he repeat? After all, he has to reply to all the points raised by her. ...*(Interruptions)*...

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir at least I have 30 years' practice and I will condense my arguments. In how many minutes do you want me to stop? I will obey you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA: As quickly as possible. It is because we do not have time now.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I want to say a few words because she has raised certain points and I have to convince her.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Then you finish in three minutes.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I will finish in five minutes because she has raised certain points. The Resolution was basically on Bihar and I personally feel that I should make a few points for her consideration and for everybody's consideration. The main issues to be dealt with in Bihar are somewhat like this: There should be a proper appraisal of the problem of Bihar even at the local-level ledaership. There should be an equitable agrarian structure in Bihar which has not been developed so far. There should be a revival of the institutions like the Panchayati Raj, the Zila Parishads and the Mandals there. The capacity of the local Planning Boards should be developed to solve their problems. The amount of money released by the Central Government should be increased. All these issues I can discuss if the honourable Member has time and I can assure her of my fullest co-operation. I really feel that she has made some good points and her Chief Minister is very competent to deal with these issues. But I really do not appreciate when we talk of the Soviet Union and India in this context. I say this because we are a highly democratic society and our founding fathers have given us certain Fundamental Rights and these have given tremendous courage to the people of this country. We are an open society and we are proud of that. Our system is to have dialogues and discussions and our House has been like that and our system has been like that. There has been and there is total democracy here and the Rule of Law prevails here. So,I could brought in these things. She should not not really appreciate when she have mentioned these two things. That is what I feel. I would invite her and her Chief Minister to come to the Planning Commission where all her problems can be dealt with.

Efforts are to be made by all concerned and there is no difficulty in solving the Bihar problem. Bihar needs a better treatment. I agree on this. Bihar needs a better treatment in view of the vast resources that it supplies to the country. To what extent the National Development Council will accommodate is a matter to be decided. The NDC will have a second round—these are the last words mentioned by the former Prime Minister and I am repeating them—and let us have a second round of discussion and we can sort out her problems. Thank you, Sir.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, may I seek a clarification from the honourable Minister?

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Sir, what about the funds allotted to Bihar under the NREP, IRDP, etc. which are not being spent? The money that was allocated under the Jawahar Rozgar Yojana has been misutilized there. What is the proposal the Central Government got to see so that this does not happen?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): That will do. Yes Mrs. Sinha you say a few wowrds but be brief.

**श्रीमती कमला सिन्हा** : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं महोदय, मैंने अपने प्रस्ताव में कुछ चर्चायें की थी । मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार में जिन नेशनल हाई वे को बनाने की बात थी और जिनको अनुमोदित किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिये धन का आबंटन नहीं किया है । मैं जानना चाहती हूं कि उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? इसी तरह से जो सिंचाई की व्यवस्था के लिये जिन परियोजनाओं को अनुमोदित किया हुआ था, उनके बारे में आप क्या करने वाले हैं ? रेल के बारे में मैंने कहा था कि कई जगह रेल पुल बनने हैं, गंगा के ऊपर पुल बनना है, रेलवे बिठानी थी, इनके बारे में अनुशंसा भी हो चुकी है, रिपोर्ट हो चुकी है, सर्वे हो चुका है, तो इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? नयी औद्योगिक संरचना के बारे में सरकार का क्या विचार है ? क्योंकि अगर अभी केंद्रीय सरकार धन नहीं देगी तो मैं आपको आगाह करना चाहती हूं कि बहुत दिनों तक यह मामला चलेगा नहीं ।

The Bihar situation is a volcanic situation.

आप संभाल नहीं पायेंगे । यह दुहाई देना कि लोकतांत्रिक पद्धति से हमारा देश चलता है और हम संघ में विश्वास करते हैं तो हम भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं । व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार ने जितना बलिदान दिया है शायद ही बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने इतना बलिदान किया हो । मैं गर्व के साथ यह बात कह सकती हूं । हमें विश्वास है कि लोकतंत्र के प्रति लेकिन यहां दो तरह की नीतियां नहीं चलेंगी । एक तरफ तो हमारे यहां से खनिज संपदा ले जायेंगे और दूसरे प्रांतों को देंगे और हमारा शोषण करेंगे । यह शोषण की प्रवृत्ति बंद करनी पड़ेगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Are you withdrawing your Resolution?

**श्रीमती कमला सिन्हा** : मंत्री जी जवाब दें, मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे

**श्री हंसराज भारद्वाज**: सारी चीजें जो आपने कहीं हैं, मैंने नोट कर ली हैं अगर आप चाहें तो इन सारी चीजों को लिखकर दे दें और जिन जिन मंत्रालयों से वे बातें संबंधित हैं, जो तरीका है उस के अनुसार मैं उनको भेज दूंगा । मैंने आपको आमंत्रित किया है कि जब भी आप बात करना चाहें, बात करें और आप कहें कि क्या स्कीम है, क्या तरीके हो सकते है । मैंने भी आपकी बातें नोट कर ली हैं और अगर आप भी लिखकर दे दें तो वह हम टेकअप करेंगे, यही मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं ।

बाकी जो बिहार के लिये फंड की बात है पब्लिक सेक्टर में जो एन्युअल प्लान 91-92 का है उसमें स्टील कोल में और नान-फेरस में, मैं इस समय डिटेल में नहीं कह सकता क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो मैं भी एक-दो घंटे बोल सकता था । मैं अनुरोध करूंगा और कहना चाहूंगा कि आपकी बात मैंने खुद नोट कर ली है। मैं आपका आदर करता हूं । मैं आपके परिवार से भी वाकिफ हूं । ऐसी बात नहीं है कि मैं बिहार के परिवारों के बारे में नहीं जानता । मैं भी 20-30 साल से राजनीति में हूं और आपके परिवार को भलीभांति जानता हूं । मैं इसीलिये आपसे बार बार कहता हूं कि आपकी जो भावनायें हैं उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। यह आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि देश का विकास होने में कुछ समय लगता है लेकिन यह विकास विचार से ही होता है । अगर आपके पास कोई नई स्कीम या कोई तरीका हो तो आज उसे सरकार को दे दें । आप जब भी चाहें मुझे मिल सकती हैं । बिहार के उत्थान के लिये आप भी कोशिश करिये, हम भी कोशिश करेंगे । प्लानिंग कमीशन यहां भी है, वहां भी है । इसके अलावा अगर आप कोई नये विचार देंगी तो हम उसको फालो करेंगे । प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन योजनाओं को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है उनको भी हम करेंगे । अगर इस पर खाली पोलिटिकल बात आपकी है तो यह

भी कह सकती हैं कि इससे हमें यह फायदा होगा, तो मैं उसको भी करने के लिये तैयार हूं । लेकिन आप इस भावना को कद्र कीजिये कि देश के निर्माण में कई चीज आपस में एक दूसरे से कहने से होती हैं । इसके लिये तरीका आप निकालिये । अगर नये तरीके हैं तो वे भी सदन के सामने रखे जा सकते हैं ।

**श्रीमती कमला सिन्हा** : महोदय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिये हैं कि हम कोआपरेशन के जरिये काम करना चाहते हैं और मुख्य संत्री को भी बुलाकर बात करेंगे और उनके साथ सलाह-मशविरा करेंगे तो मंत्री जी के इन आश्वासनों पर भरोसा करके क्योंकि वे इस सेदन के सदस्य भी हैं, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

*The Resolution was, by leave, withdrawn.*

---

**STATEMENT(S) BY MINISTER(S)**

**Submission of report by the National Commission on Rural Labour**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now, the Labour Minister to make a statement regarding submission of report by the National Commission on Rural Labour.

**डा. रत्नाकर पाण्डेय** (उत्तर प्रदेश): आज शुक्रवार का दिन है, सब को बाहर जाना है । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाउस को एडजर्न कर दिया जाये और फिर सोमवार से विधिवत कार्यवाही चलाएं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKA): We have many things. Let the Minister make his statement and then we shall...

DR. RATNAKAR PANDEY: No clarifications, Sir. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Let us see.

SOME HON. MEMBERS: Statement on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Clarifications on Monday. (*Interruptions*). Let me take the sence of the House. Will the clarifications be sought by the Members today?

SOME HON. MEMBERS: No, no. On Monday.

DR. RATNAKAR PANDEY: We will study the statement and seek clarifications on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Let me take the sence of the House on this also. There are three statements today.

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): I have a submission to make. The House is already discussing the functioning of the Ministry of Labour. Can it be clubbed together so, that whatever... (*Interruptions*).

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): It is a *suo motu* statement. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): All right. The Minister will give reply on the clarificatiosn sought, on Monday. (*Interruptions*).

SHRI P. A. SANGMA: The Government had set up a National Commission on Rural Labour in August, 1987 to study and report on the economic, social and working condition of Rural Labour in the context of changing socio-econnomic framework in the rural areas. The Commission was also to study the existing legislative provisions intended to protect the interests of rural labour and suggest measures to make them more effective.

The Commission have submitted their report to the Government on 31-7-1991. The report contains a large number of recommendations regarding general developmental eff-